

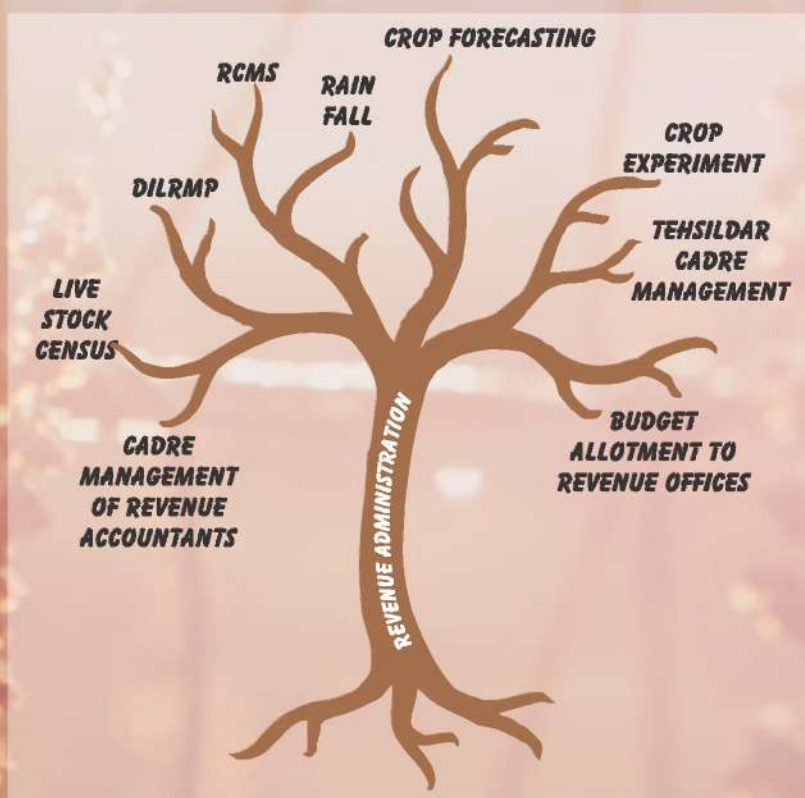
राविरा

अंक 118

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी



APEX COURT FOR ALL REVENUE COURTS IN RAJASTHAN



राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्व मण्डल में गणतंत्र दिवस समारोह वर्ष 2019



संरक्षक

श्री मुकेश शर्मा

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

श्री मोडूदान देशा, सदस्य

श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

श्री महावीर सिंह, सदस्य

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

श्री धूकल राम कसवाँ, सदस्य

वरिष्ठ संपादक

विनीता श्रीवास्तव

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक

(प्रभारी अधिकारी, राविरा)

पवन कुमार शर्मा

जन सम्पर्क अधिकारी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग

जानकी कुमार सोलीवाल

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

(सेवानिवृत्त)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

गफूर अली

वरिष्ठ सहायक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर



राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक-118

रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से

2. संपादकीय

लेख-सामग्री एवं विविध जानकारी

3. भू-राजस्व प्रशासन के वैज्ञानिक 1

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 9

प्रमुख धाराएं एवं उन पर राजस्व मंडल
के निर्णय

स्थायी स्तम्भ

5. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 13

6. राजस्व अधिकारियों के वाद 72

निस्तारण : मण्डल की

वार्षिक समीक्षा

7. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र 89

एवं संशोधनादि

8. राजस्व समाचार 97

अन्य

9. कविता 100

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।



अध्यक्ष की कलम से...

राजस्थान में विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। राजस्व मंडल के स्तर पर बीते वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 10,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका। यह समयबद्धता से राजस्व न्यायालयों के आयोजन के साथ ही लोक राहत के प्रति राजस्व प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। राज्य में प्रत्येक राजस्व न्यायालय स्तर पर लक्ष्य तय करते हुए नियमित न्यायालय के आयोजन से लंबित वादों के निस्तारण के लिए अधिकारियों के स्तर पर गंभीरता दिखानी होगी।

राजस्व मंडल ने राजस्व न्यायालय प्रबंधन के तहत राजस्व न्यायालयों की ऑनलाइन ग्रीड स्थापित करते हुए आरसीएमएस पोर्टल की सुविधा आमजन के लिए प्रदान की है, इससे राजस्व वादों की अद्यतन स्थिति कहीं भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इन समन्वित एवं नवाचारी प्रयासों से महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं न्यायिक कार्यप्रणाली को जन-जन तक पहुंचाने में आशानुरूप पारदर्शिता भी आई है।

राजस्थान राज्य में आम जनता का समयबद्धता व सुलभता से त्वरित राहत प्रदान करना लोक सेवा क्षेत्र का प्रमुख दायित्व है। राजस्व न्यायालय क्षेत्र की सेवाओं को गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ लोक कल्याण का पूरक बनाने के लिए हमें हर स्तर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करनी होगी। हमारे समक्ष आने

वाले प्रकरण, आवेदन अथवा लोक राहत प्रदान के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन का उसकी गंभीरता के आधार पर निस्तारण करना हमारा लक्ष्य हो।

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सरकार की ओर से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान की गई है, जिसका मूल उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाते हुए भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकना है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें अधिनियम के उल्लंघन पर दंडनीय प्रावधान भी रखे हुए हैं, ऐसे में सरकार की लोक कल्याण की मूल भावना के अनुरूप हमारी सेवाओं को गुणवत्ता के साथ आमजन तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोक सेवा के बेहतर क्रियान्वयन का संकल्प लेकर आप सब राज्य को अनुकरणीय बनाने में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ।

(मुकेश कुमार शर्मा)

अध्यक्ष



संपादकीय..



राविरा के सुधि पाठकगण !

राजस्थान में विगत लंबे अंतराल से लंबित राजस्व वादों के रिकॉर्ड निस्तारण से राजस्व मंडल एवं विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों की सक्रिय एवं सराहनीय भागीदारी एवं सतत प्रयासों के लिए आप सभी को बधाई।

राजस्व मंडल की ओर से लागू किए गए आरसीएमएस ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन, ईमित्र प्लस, डिजिटलाइजेशन, ई साइनिंग व ई फाइलिंग सेवाएं राजस्व न्यायालयों के कार्य निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त कदम साबित हो रही हैं। राजस्व मंडल की ओर से नियमित कोर्ट्स लगाए जाने के सूत्र को जिला स्तरीय राजस्व न्यायालयों को भी गंभीर होकर अपनाए जाने की जरूरत है, जिससे लोक राहत के क्षेत्र में राज्य अदद पहचान बना सके।

राविरा का 118वाँ अंक महत्वपूर्ण सामग्री के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही आपसे अपेक्षा है कि राविरा के लिए विशेष अनुभव एवं आलेख हमें नियमित तौर पर हमें भेजते रहें ताकि उनका लाभ इस क्षेत्र में दी जा रही सेवाओं में मिल सके।

प्रसन्नता का विषय है कि राजस्व मंडल की ओर से आयोजित विभिन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में राज्य के बड़ी तादाद में पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे कार्मिकों को विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गई। इनमें तहसीलदार के लिए 46 पदों पर पदोन्नति की गई जिनमें 28 नायब तहसीलदार तथा 18 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार बनाया गया। इसी प्रकार 32 कार्मिकों को कार्यालय अधीक्षक व 16 सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया वहीं 33 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक तथा चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

भू अभिलेख नियमों में संशोधन उपरांत पटवारियों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित की जाकर ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवाएं देने वाले 899 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार राजस्थान में 4370 अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर नियुक्ति के लिये जिला आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

विनीता श्रीवास्तव

निबंधक

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम



तत्कालीन राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री वी. श्रीनिवास की मौजूदगी में आयोजित निजी सचिव श्री भुवनचन्द्र एवं जमादार श्री भैरोंसिंह का सेवानिवृत्ति समारोह दिनांक 30-11-2018



सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए मंडल सदस्य श्री मोडूदान देथा दिनांक 31-12-2018

राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम दिनांक 28-02-2019



राजस्व मंडल सदस्य श्री चिरंजीलाल दायमा संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)
श्री भंवरलाल को उनके सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुये।



राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम दिनांक 28-02-2019



मंडल सदस्य श्री मनोज कुमार नाग संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) श्री भंवरलाल को उनके सेवानिवृत्ति पर धार्मिक पुस्तक 'गीता' प्रदान करते हुये।



राजस्व मंडल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम दिनांक 28-02-2019



माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार नाग एवं श्री चिरंजीलाल दायमा निजी सचिव श्री कैलाश वैष्णव को उनकी सेवानिवृत्ति पर क्रमशः धार्मिक पुस्तक 'गीता' एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुये।



भू-राजस्व प्रशासन के वैज्ञानिक (Scientist of Revenue Administration)



—डॉ. गिरवर सिंह राठौड़
(सेवानिवृत्त तहसीलदार)

भारतीय भूमि प्रशासन के वैज्ञानिक (Indian Scientist of land Administration)

लोक प्रशासन के अन्तर्गत भू-राजस्व प्रशासन (भू-अभिलेख) का अध्ययन अनुशीलन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। भू-राजस्व प्रशासन का विकास प्राचीन समय से निरन्तर जारी है ऐसे में आवश्यक है कि विषय से संबंधित प्रमुख विद्वानों (Eminent Scientist) का परिचय कराया जाये, जिन्होंने भू-राजस्व के क्षेत्र में अध्ययन विषय व व्यावहारिक प्रक्रिया के विकास में योगदान दिया है। भू-राजस्व प्रशासन के प्रमुख वैज्ञानिक जिन्होंने भू-राजस्व प्रशासन के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान की, को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम भाग में वे जिन्होंने भू-राजस्व प्रशासन को एक अध्ययन विषय के रूप में पहचान दी।
द्वितीय वे जिन्होंने भू-राजस्व प्रशासन की व्यावहारिक प्रक्रियाओं (Practical Procedure) को एक व्यवस्थित रूप (Systemetic) प्रदान किया।

1. भू-राजस्व प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले वैज्ञानिक :-

कौटिल्य (Kautilya)	“अर्थशास्त्र” (प्राचीन समय का भू-राजस्व प्रशासन)
अबुल फज़ल (Abul Fazal)	“आइना-ए-अकबरी” व “अकबरनामा” (मुगलकालीन भू-राजस्व प्रशासन)
बडेन पावेल (Baden Pawel)	“The Land Systems of British India” (ब्रिटिश समय का भू-राजस्व प्रशासन)
मोरलेण्ड (Morlend)	“The Revenue Administration of the United Provinces” (ब्रिटिश समय का भू-राजस्व प्रशासन)
जे. डी. शुक्ला (J.D. Shukla)	(State and District Administration in India) (आधुनिक समय के भू-राजस्व प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन)

2. भू-प्रशासन की व्यावहारिक प्रक्रिया के क्षेत्र योगदान देने वाले विद्वान प्रमुख हैं :-

- राजा टोडरमल भूमि (बन्दोबस्त व्यवस्था के जनक) (Father of Settelement System)
- वारेनन हैस्टिंग्स (1732- 1818) (भारत में प्रारम्भिक राजस्व नीति के प्रतिपादक) (Early Exponent of land revenue policy in India)

- चार्ल्स कॉर्नवालिस (1738-1805) (बंगाल में जमींदारी भूमि व्यवस्था (स्थायी बन्दोबस्त) का जन्मदाता) (Generator of Permanent Settlement in Bengal)
- होल्ट मैकेन्जी (भारत में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था के जनक) (Generator of Raitwari Land System in India)
- थॉमस मुनरो (दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के विकासकर्ता)

उपर्युक्त विद्वानों के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख इस प्रकार है :-

कौटिल्य :- भारत के भू-राजस्व के प्रशासनिक इतिहास में कौटिल्य को एक महान् चिन्तक माना जाता है। कौटिल्य अथवा चाणक्य, जिन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है, की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना ‘‘अर्थशास्त्र’’ है, जो सम्भवतः तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है, मैसूर के डॉ. आर. श्यामशास्त्री को 1904 में अर्थशास्त्री की हस्तलिखित पाण्डुलिपि प्राप्त हुई डॉ. श्याम शास्त्री ने 1909 में इसका प्रकाशन करवाया तथा 1915 में इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ।

अर्थशास्त्र में भू-राजस्व की विवेचना ‘राष्ट्र’ के अन्तर्गत निम्न मदों (Heads) में की गयी है :-

- सीता (राजा के कृषि क्षेत्रों की उपज) ;
- भाग (राजा को) प्राप्त होने वाला उपज का भाग ;

अर्थशास्त्र में जहाँ कृषि भूमि पर लगाए जाने वाले अन्य करों ग्राम-चरागाहों और सीमाओं से प्राप्त राजस्व, राजस्व मुक्त भू-खण्ड व कर्मचारियों का प्रदत्त भू-खण्ड आदि की विवेचना की गयी है। वहीं भू-राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत कार्मिक/अधिकारियों के पारिश्रमिक का भी उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र में वर्णित विविध राजस्व अधिकारी के कार्यों में भू-राजस्व के निर्धारण तथा वसूली (संग्रहण) के स्रोतों पर प्रकाश डाला गया है। कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राजकीय आय का समावेश किया गया है।

इसमें राजस्व प्रशासन के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता ‘गोप’ का विशेष उल्लेख। जिस पर उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। अर्थशास्त्र में भू-राजस्व के निर्धारण के लिए खेतों की ‘‘माप’’ राजकीय अधिकारियों द्वारा की जाती थी का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में न केवल भू-राजस्व की विविध शाखाओं की वर्गीकृत सूची और भू-राजस्व निर्धारण के सिद्धान्त दिये गये हैं, अपितु उसमें अंकित दैनंदिन प्रशासन और राज्य की आपातकालीन स्थितियों के वर्णन में सुनिश्चित अर्थशास्त्र में कृषि नीति की रूपरेखा भी खोजी जा सकती है। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य कृषकों के साथ कठोर अथवा क्रूर व्यवहार न करते हुए राजकोष की वृद्धि के लिए राज्य के साधन सम्पत्ति का पूर्णतया उपयोग करना था।

इस प्रकार भू-राजस्व प्रशासनिक इतिहास में कौटिल्य को एक महान चिन्तक माना जा सकता है। अर्थशास्त्र जो ई. पूर्व तीसरी शताब्दी में लिखी गई थी को प्राचीन भारतीय भू-राजस्व व्यवस्था का सर्वाधिक वैज्ञानिक ग्रन्थ माना जाता है।

अबुल फजल की आईना-ए-अकबरी :- भूमि प्रशासन संबंधी सूचना का एक मुगलकालीन स्रोत आईना-ए-अकबरी है, जिसके लेखक अबुल-फजल सलामी (Abul Fazal Sallami) को माना जाता है, जबकि वास्तविकता में यह विभिन्न लेखकों तथा स्रोतों का संकलन है, जो अबुल फजल द्वारा किया गया सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की यह हस्तलिखित पुस्तक है जिसमें वर्णनात्मक रूप में राजस्व के विभिन्न विवरण हैं। सरकार, परगना की राजस्व माँग, विभिन्न जातियों के वर्गों की तालिका जिनसे राजस्व प्राप्त किया गया था आदि का उल्लेख है। आईना-ए-अकबरी में प्रदत्त आँकड़ों से मुगलकाल में राजस्व भुगतान के विभाजन का एक चित्र प्राप्त किया जा सकता है। “दाम” (एक रुपए का चालीसवाँ भाग) में प्रस्तुत भारत में भू-राजस्व की मुगलकालीन माँग का उल्लेख आईना-ए-अकबरी में है।

अबुल फजल के अनुसार “राजपद ईश्वर का एक उपहार है और यह तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि एक व्यक्ति में हजारों महान गुणों और विशेषताओं का समन्वय न हो जाये। इस महान पद के लिए जाति, धन-सम्पत्ति तथा लोगों की भीड़-भाड़ ही काफी नहीं है।”

भू-राजस्व प्रशासन की प्रकृति और उद्भव तथा मुगलकालीन राजस्व प्रशासन से परिचय प्राप्त करने हेतु 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में अबुल-फजल द्वारा लिखित आईना-ए-अकबरी व अकबर नामा महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। भू-राजस्व प्रशासन के सन्दर्भ में इन पूर्ववर्ती कृतियों के अपेक्षित प्रमाणों का परीक्षणकार उन्हें समकालीन प्रमाणों से सहबद्ध किया गया है। “फारसी” में लिखी उस समय किये “प्रसिद्ध” रचनाएँ हैं।

भू-राजस्व प्रशासन की व्यावहारिक प्रक्रियाओं (Practical Procedure) में योगदान करने वाले वैज्ञानिक :-

राजा टोडरमल (Todarmal)

अकबर के समय भू-राजस्व प्रशासन में जमीनी स्तर पर आधुनिक व्यवस्था का श्रीगणेश करने का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। टोडरमल ने पहली बार राजस्व प्रशासन में भूमि की उचित ‘नाप जोख’ तथा खेतों की कुल असल पैदावार को आँकने के आधार पर कर निर्धारण के दरों की अनुसूची तैयार की गयी जिसे मालगुजारी बन्दोबस्त जो 1580 ई. में ‘आइने दहसाल’ आज्ञापत्र द्वारा जारी किया गया था के अन्तर्गत साम्राज्य की सम्पूर्ण भूमि एक समान माप प्रणाली द्वारा सिकन्दर लोदी के गज (41 अंगुल या 33 इंच) के आधार पर नापी गयी व गज-माप पर आधारित आधुनिक भू-राजस्व प्रशासन का भूमि माप उपकरण “जरीब” का आविष्कार किया। भूमि की माप के आधार पर भूमि का वर्ग तय कर काश्तकार पर कर लगाने का यह प्रयोग राजा टोडरमल द्वारा ही किया गया।

“राजा टोडरमल को आधुनिक भू-राजस्व प्रशासन का जन्मदाता कहा जा सकता है जिन्होंने भू-राजस्व प्रशासन को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कमो-बेश के रूप में आज भी भारत में टोडरमल द्वारा स्थापित भू-राजस्व की व्यवस्था विद्यमान है।”

वारेन हैस्टिंग्स¹¹ (1732-1818) (Warren Hastings)

18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अकबर तथा अन्य मुगल सम्राटों की स्थापित की हुई भूमि कर व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, वारेन हैस्टिंग्स का विश्वास था कि समस्त भूमि शासक की है,

जमींदारों को कर संग्रहकर्ता मान समस्त अनिश्चित संयुक्त तथा पुश्तैनी अधिकारों की अवहेलना की गई तथा जमींदारों को केवल कमीशन (Commission) का ही अधिकार दिया।

सन्तोषजनक राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध परीक्षण तथा अशुद्धि (Trial and Error) का नियम बनाया। राजस्व प्रशासन में कलेक्टर (Collector) के पद की स्थापना (1772) करने का श्रेय वारेन हैस्टिंग्स को तथा भारत में प्रथम ब्रिटिश राजस्व नीति (Revenue Policy) निर्माण का श्रेय हैस्टिंग्स को जाता है।

चार्ल्स कॉर्नवालिस (Cornwallis) (1738-1805)

कॉर्नवालिस को आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा समाधान करें जिससे कम्पनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। कॉर्नवालिस भारत में भूमि प्रशासन के क्षेत्र में स्थाई जमींदारी व्यवस्था (The Permanent Zamindari Settlement) के जन्मदाता थे जिसके अन्तर्गत जमींदार को (जो प्रायः भूमि कर संग्रहकर्ता ही होता था) भूमि का स्वामी स्वीकार कर उसे भूमि के विक्रय, रहन, अथवा दान देने का अधिकार दिया गया। शासन ने भूमि कर देने हेतु जमींदारों को ही उत्तरदायी बनाया। इस प्रकार चार्ल्स कॉर्नवालिस को भू-राजस्व प्रशासन में एक नया प्रयोग स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) करने का श्रेय दिया जाता है।

कॉर्नल रेड (Col Read)

भारत में आधुनिक भू-धारण पद्धति (Land Tenure System) 'रैयतवाड़ी व्यवस्था' (Raitwari System) को लागू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में बम्बई प्रान्त में भी लागू कर दिया गया जिसे स्वतंत्र भारत में अपनाया गया।

होल्ड मैकेन्जी :- आयुक्तों के बोर्ड के सचिव होल्ड मैकेन्जी ने 1819 में सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाये, भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाये ग्राम भू-राजस्व को निर्धारित कर, भूमि कर संग्रह (Land Revenue Collection) करने की व्यवस्था लम्बरदार को दी जाये। उक्त होल्ड मैकेन्जी के सुझावों को रेव्यूलेशन एक्ट 1922 द्वारा सुझावों को कानूनी रूप दे दिया गया। होल्ड मैकेन्जी के उक्त सुझाव अनुसार भारत में पहली बार भूमि (खेतों) के मानचित्र तथा पंजिकाओं के अनुसार भारत में मानचित्र तथा पंजिकाओं (Registers) का निर्माण अर्थात् भू-अभिलेख का निर्माण मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया। इन्हें भारत में आधुनिक भू-अभिलेख के जन्मदाता कहा जा सकता है।

संभवतया भारतीय प्रशासन के अन्तर्गत भूमि प्रशासन (भू-राजस्व प्रशासन) एक ऐसा विषय रहा है, जिसके अनुसंधान अध्ययन (Research Study) में शोधार्थियों ने कम ही रुचि ली है, यही कारण है कि इस विषय पर स्वतंत्र भारत में समग्र रूप से आज तक शोध अध्ययन नहीं हुआ और अगर कुछ अनुसंधान अध्ययन हुआ भी है, तो वह भूमि प्रशासन के एक विषय या क्षेत्रीय आधार पर ही किया गया है।

भू-राजस्व व भू-अभिलेख प्रशासन के क्षेत्र में किये गये अध्ययन कार्य को निम्नानुसार बनाया जा सकता है।

1. प्राचीन हिन्दू राजस्व व्यवस्था का विस्तार से ऐतिहासिक विवेचना श्री उपेंद्रनाथ घोषाल (1929) द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य "कन्ट्रीब्यूशन्स टू दि हिस्ट्री ऑफ दि रेवेन्यू सिस्टम" शीर्षक से कलकता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ इसमें प्राचीन हिन्दू राजस्व व्यवस्था का विशद विश्लेषण किया गया है।
2. ब्रिटिश भारत में (1892) "भू-राजस्व प्रशासन विषय पर एक मात्र भारतीय स्तर पर गहन और विस्तृत रूप से किया गया अध्ययन कार्य का श्रेय बी.एच. बंडन¹⁶ पावेल को जाता है। उन्होंने अपने ग्रन्थ "The Land Systems of British India" में सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र विशेष रूप से बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रान्त (Provinces) व अवध, अजमेर, मारवाड़, केन्द्रीय प्रान्त (Central Provinces) पंजाब, मद्रास, बम्बई, बरार, (Berar) असम, कुर्ग (Coorg) तथा बर्मा (म्यानमार) प्रान्तों/क्षेत्रों में भू-राजस्व प्रशासन की भू-धारण पद्धति (Land Tenures), भू-राजस्व (Land Revenue) मालगुजारी बन्दोबस्त (Land Revenue Settlement) स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlements), महालवारी बन्दोबस्त (Mahalwari or Village Settlements) रैयतवाड़ी बन्दोबस्त (Raiyatwari Settlements) तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित भू-राजस्व अधिकारी (Land Revenue Officers) भू-राजस्व की संक्रियाएँ (Land Revenue Business and Procedure), भूमिधारी (Land holder) भूमि अभिधारी (Land Tenant) आदि का गहन, विस्तृत व वास्तविक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

पावेल के उपर्युक्त ग्रन्थ का गहनता से अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भू-राजस्व प्रशासन का कोई भी पक्ष उनके अध्ययन क्षेत्र से वंचित नहीं रहा है। पावेल जो कि एक विदेशी विद्वान थे ने प्रशासन की इस शाखा को जिसमें अरबी, फारसी व उर्दू शब्दों का प्रभुत्व है, तथा जिन्हें समझना आसान कार्य नहीं है, उन्हें बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करने का अद्भुत कार्य किया है।

पावेल के द्वारा भू-राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में किये गये अध्ययन की तुलना अगर लोक प्रशासन के विद्वान प्रो. फ्रेडविलियम रिग्ज (F.W. Riggs) द्वारा प्रतिपादित समयाश्र्वीय समाज (Prismatic Society of Sala Mode) से की जाए तो उनका विश्लेषण व विशेषताएँ विकासशील देशों के संदर्भ में एक विदेशी विद्वान होते हुए भी जिस गहराई व सूक्ष्मता से की है, उसी प्रकार की सूक्ष्मता व गहराई पावेल के अध्ययन में दृष्टिगोचर होती है।

पावेल द्वारा किया गया भारत के विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न भूमि व्यवस्थाओं का समग्र अध्ययन तो किया लेकिन इसमें भी तुलनात्मक विश्लेषण का अभाव देखा जा सकता है। पावेल ने अपने अध्ययन को उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ 'Land systems of British India' जो तीन खण्डों में 1892 में प्रकाशित की।

इसके उपरान्त पावेल ने अपनी दूसरी रचना "Administration of Land Revenue and Tenure in British India" (1907) में भू-राजस्व प्रशासन से संबंधित विषयों को सार (Summary) के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें भी तुलनात्मक विश्लेषण का अभाव रहा है। पावेल की तीसरी

रचना में भारतीय ग्राम समुदाय की विस्तृत विवेचना की गई है।

3. भू-राजस्व प्रशासन के दूसरे प्रमुख विद्वान रहे हैं डब्ल्यू. एच. मोरलेण्ड²⁰ इन्होंने अपनी पुस्तक "The Revenue Administration of the united provinces" (Principles and the development of the Revenue Administration of the united Provinces)²¹ 1911 में राजस्व-प्रशासन का ऐतिहासिक पक्ष, काश्तकारी विधि (Tenancy Legislation) भू-अभिलेख, भू-अभिलेख कार्मिक, नक्शा व खसरा, जमाबन्दी लम्बरदार, अधिकार अभिलेख (Record of Cultivating Rights) भू-राजस्व संग्रहण, आदि भू-राजस्व संबंधी विषयों का विवरण प्रस्तुत किया है, लेकिन मोरलेण्ड का यह अध्ययन केवल संयुक्त प्रान्तों तक ही सीमित रहा है।
4. भू-राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में एस.सी. रॉय (1915) की कृति ("Land Revenue Administration in India")²² में भू-राजस्व व भूमि अभिधारी भू-राजस्व सर्वे एवं भू-प्रबन्ध भूमि विधियाँ, भू-अभिलेख आदि विषयों की विवेचना बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब व संयुक्त प्रान्तों में तुलनात्मक रूप से किया है, लेकिन श्री एस.सी. रॉय की यह कृति अधिकांश रूप में विभिन्न प्रतिवेदनों पर आधारित है।
5. स्वतंत्र भारत में पटना विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के डॉ. द्विजेन्द्र नारायण झा का शोध प्रबन्ध 1964 'मौर्योत्तर तथा गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था'²³ (Revenue System in Post Mauryan and Gupta times) भू-राजस्व प्रशासन के विषय भू-स्वामित्व तथा राजा का कराधान अधिकार, भू-राजस्व, राजभूमि (खालिसा) राजस्व अधिकारियों का ऐतिहासिक, अध्ययन विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। जिसमें प्राचीन समय में भारत में भू-राजस्व प्रशासन की व्यवस्था का ज्ञान होता है।
6. मुगलकाल में भू-राजस्व प्रशासन का समग्र अध्ययन का श्रेय नोमान अहमद सिद्दीकी कृति "मुगलकालीन भू-राजस्व प्रशासन 1700-1750" को जाता है। श्री सिद्दीकी ने इस कृति में मुगलकालीन समय में ग्राम एवं कृषकों की स्थिति, जमींदार और जमींदारी व्यवस्था, भू-राजस्व की माँग तथा राजस्व निर्धारण की पद्धतियाँ भू-राजस्व प्रशासन, भू-राजस्व का विभाजन, आदि का विशद रूप से विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में श्री सिद्दीकी ने आइना-ए-अकबरी, अकबरनामा जैसी कृतियों और सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी की घटनाओं के विवरणों का विस्तृत अध्ययन सम्मिलित किया है। इस कृति का सम्बन्ध मुगल भू-राजस्व प्रशासन के विविध पहलुओं से है।
7. जे.डी. शुक्ल (J.D. Sukla) :- स्वतंत्र भारत में स्व. जे. डी. शुक्ला की कृति "State and District Administration in India"²⁵ ने भू-राजस्व प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद शुक्ला पहले विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भू-राजस्व प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। यही कारण है कि श्री शुक्ला की कृति भू-

- राजस्व प्रशासन विषय में एक पाठ्यपुस्तक (Textbook) के रूप में स्थान रखती है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि प्रबन्ध के अधिकांश विषयों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का श्रेय लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान जे.डी. शुक्ला²⁶ की कृति "State and District Administration in India"²⁷ को जाता है। इसमें भू-राजस्व प्रशासन का भारत में जिला व राज्य प्रशासन का गहन, विस्तृत व तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। श्री शुक्ला ने भू-राजस्व प्रशासन से संबंधित विषय भूमि व्यवस्था, भू-प्रबन्ध (Settlement) पटवारी, भू-अभिलेख, कानूनगो, तहसीलदार शेष भारत में बंगला व बिहार में भू-राजस्व प्रशासन के भिन्नता पंजाब व्यवस्था, उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर का समग्र रूप से मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।
8. जे.डी. शुक्ला के उपरान्त भूमि प्रशासन और उसके विभिन्न पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन अगर किया गया है तो वह डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ द्वारा है। डॉ. राठौड़ ने भारत में भूमि प्रशासन के अन्तर्गत निम्न पुस्तकों की रचना की है²⁸ :-
- **भारत में भूमि प्रशासन की संरचना (2008)** (Land Administration Structure in India) पंचशील प्रशासन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302 003, 2008, इस कृति में लेखक ने भूमि प्रशासन के विविध पक्षों का गहनता और सूक्ष्मता से अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति में लेखक ने भूमि प्रशासन की अवधारणा, भूमि प्रशासन से सम्बद्ध प्रबन्धन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, भूमि सुधार आदि की विशद व्याख्या की है। भूमि प्रशासन का सार प्रस्तुत करते हुए लेखक ने भूमि-प्रशासन से सम्बन्धित तकनीकी शब्दावली का सरल परिचय दिया। इस कृति से पाठक भूमि-प्रशासन सम्बन्धी जानकारीयों की बारीकियों को समझ सकता है।
 - **भूमि विधियाँ एवं राजस्व न्यायालय प्रशासन (2008)** (Land Law's and Revenue Courts Administration) पंचशील प्रशासन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003, इसी श्रृंखला की कृति 'भूमि विधियाँ तथा राजस्व न्यायालय प्रशासन' में विद्वान लेखक ने उन सभी नियमों और कानूनों की विधिवत विवेचना की है, जिनका सम्बन्ध भूमि प्रशासन व्यवस्था से है। यह कृति पाठक के समक्ष भूमि सुधारों के अन्तर्गत बनने वाले नियमों और कानूनों की व्यवस्था करती है। इससे भूमि से सम्बन्ध रखने वाला हर व्यक्ति भू-राजस्व नियमों के विषय में जागरूक हो सकता है।
 - **भूमि सुधार एवं भूमि प्रशासनिक व्यवस्था (2008)** (Land Reform & Land Administrative System) पंचशील प्रशासन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302 003, 2008, इसी श्रृंखला की कृति 'भूमि सुधार एवं भूमि प्रशासनिक व्यवस्था' भूमि सुधार, भू-राजस्व नियम और कानून, भू-राजस्व प्रशासन आदि पर समग्र रूप से विचार करती है। विद्वान लेखक ने अपने विशद और गहन अध्ययन द्वारा भूमि सुधार और भूमि प्रशासनिक

व्यवस्था के सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और तुलनात्मक पक्षों का उद्घाटन किया है। यह कृति भूमि सुधार तथा भूमि प्रशासन के विषय में पाठकों की जिज्ञासाओं का शमन करेगी।

- **भूमि व्यवस्था एवं भू-प्रबन्ध प्रशासन (2008)**, (Land System and Land Settlement Administration) पंचशील प्रशासन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर - 302 003, 2008, इसी श्रृंखला की कृति "भूमि व्यवस्था एवं भूमि प्रबन्ध प्रशासन" के अन्तर्गत विद्वान लेखक ने भूमि व्यवस्था एवं उसके प्रशासन से सम्बन्धित सभी पक्षों का गहनता और सूक्ष्मता से अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति के पारायण से पाठक को भू-स्वामित्व की अवधारणा, भू-धारण की पद्धतियों तथा भूमि प्रशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विशद जानकारी हो सकती है। इस पुस्तक को पढ़कर पाठक सरलता से भू-प्रबन्ध की समीक्षा एवं विवेचना कर सकता है।
- **भू-राजस्व एवं भू अभिलेख प्रशासन (2008)** (Land Revenue & Land Record Administration) पंचशील प्रशासन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302 003, 2008, इसी श्रृंखला की कृति "भू-राजस्व एवं भू-अभिलेख प्रशासन" में विद्वान लेखक ने भू-राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित सभी पक्षों का सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति से पाठक भू-राजस्व प्रशासन की सभी बारीकियों को स्पष्टता के साथ समझ सकता है।
- राजस्थान में तहसील प्रशासन, मित्तल पब्लिकेशन दिल्ली 35, 1988, प्रस्तुत ग्रंथ भारत में भू-राजस्व प्रशासन के समग्र दिग्दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। यह पुस्तक विश्वविद्यालय, राज्य प्रशासन के नीति निर्माताओं, विशेष रूप से भू-राजस्व से सम्बन्धित नीतियाँ, प्रशासनिक अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं व अनुसंधान छात्रों एवं राजस्व प्रशासन में रुचि रखने वाले जागरूक नागरिकों की उत्कंठा को पूर्ण कर सकने में पर्याप्त सक्षम हो सकेगी।
- वर्तमान में स्वयं लेखक भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्था, नई दिल्ली (ICSSR) से Senior Fellow के रूप में भूमि प्रशासन के अन्तर्गत भारत में भूमि अभिलेख की संरचना (Anatomy of Land Record Administration in India) पर शोध कार्य कर रहा है।



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं एवं उन पर राजस्व मण्डल के निर्णय

-श्री शंकर लाल बलाई
तहसीलदार, राजस्व मंडल

धारा - 42 (ख)

बिक्री, दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबन्ध :- बिक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं है पर सामान्य प्रतिबन्ध है।

निर्णय

- 1- यदि बेचान और सब प्रकार से ठीक है, और अन्तरिती का कब्जा हो जाये तो सम्पत्ति और अन्तरिती का कब्जा हो जावे तो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53-क के कारण रजिस्ट्री नहीं कराने से ही विक्रय पत्र अवैध नहीं हो जाता। बिना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र अन्तरण की किस्म की साक्ष्य के लिए साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य है। (1955 RRD 472)
- 2- खातेदारी भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, किन्तु खातेदारी अधिकार हो हस्तांतरणीय। (1964 RRD 301)
- 3- काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1964 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित इस धारा का खण्ड (ख) भूत लक्षी नहीं है। (1964 RRD 935)
- 4- इस धारा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों को जो कि ऐसी जातियों के सदस्य नहीं हैं, खातेदारी अधिकारों के हस्तांतरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध भारतीय संविधान के प्रतिकूल नहीं है। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने का उचित स्थल राजस्व मण्डल नहीं है। (1964 RRD 209)
- 5- इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किये गये हस्तांतरण के आधार पर चाहा गया नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तथा अपर समाहर्ता व राजस्व अपील अधिकारी दोनों ने उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत न कर केवलमात्र अवधि के प्रश्न पर अपील अस्वीकार करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालयों को मौलिक कानून जो कि इस धारा में दिया गया है, का

- ध्यान रखना चाहिए या जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों / जनजातियों के हितों की सुरक्षा की गई हैं। अतः इन अधिकारियों को इस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिये थी जिससे कि उपरोक्त प्रावधान लागू हो सकता। (1964 RRD393)
- 6- यह धारा केवल खातेदार असामियों तक ही सीमित है। शब्द "भूमि" और "भूमि में हित" समानार्थी हैं। (1964 RRD 301)
- 7- कृषि भूमि का मकान बनाने के लिये अन्तरण अवैध है जब तक कि उसे पहले नगरीय भूमि में परिवर्तित नहीं करा लिया गया हो। (1972 RRD266)
- 8- जहां विक्रय पूरे खसरे का नहीं हो तो उस धारा के उपबन्ध लागू होंगे। (1976 RRD419)
- 9- हर हालत में अनुसूचित जाति के सदस्य इस धारा के संरक्षण के हकदार हैं। (1977 RRD 200)
- 10- सन् 1964 से पूर्व के विक्रय शून्य न होकर शून्य करणीय (viodable) थे और क्रेताओं को बिना कानूनी कार्यवाही के बेदखल नहीं किया जा सकता। (1979 RRD494)
- 11- अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा 20.8.56 से पूर्व गैर अनुसूचित जाति / जनजाति वालों के किये गये विक्रय वैध थे। (1980 RRD 601)
- 12- यदि विक्रय अन्य प्रकार से ठीक है तो कब्जा न देने पर भी यह विधिमन्य है और विक्रेता को धारा 183 के तहत बेदखल किया जा सकता है। (1981 RRD14)
- 13- ईसाई बनने पर भी इस धारा का संरक्षण मिलता है। (1981 RRD420)
- 14- अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति / जनजाति को किया गया विक्रय इस धारा का उल्लंघन करता है चाहे उसे सेटलमेन्ट अभिलेख में दर्ज कर दिया गया हो। (1982 RRD283)
- 15- जहां धर्म परिवर्तन छल मात्र से ही किया गया हो, यह धारा लागू होती है। (1983 RRD 836)
- 16- अन्तरण के अन्तर्गत समझौता डिक्री तथा सविरोध डिक्री भी सम्मिलित है। (1983 RRD159)
- 17- जहां अन्तरित खण्ड धारा 53 के अन्तर्गत विहित न्यूनतम क्षेत्र से भी कम हो तो यह भी देखा जाना चाहिए कि वह किसी समीपवर्ती सर्वेनम्बर में विलीन हुआ या नहीं। (1984 RRD 578)

- 18- अनुसूचित जाति/जनजाति वालों की भूमि दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज होने पर भी सरकार के नाम दर्ज कर दी जानी चाहिए। (1984 RRD184)
- 19- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दीगर अनुसूचित जाति या दीगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरण चाहे उसकी स्वीकृति से ही हो, अवैधानिक है। (1992 RRD601)
- 20- अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया विक्रय धारा 42 (ख) के विरुद्ध है एवं ऐसा विक्रय शून्य एवं अवैध है। (1993 RRD94)
- 21- अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि को जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, ने 1950 में खरीद की और उसका नामान्तरण 1957 में (धारा 42 लागू होने के बाद) उक्त विक्रय एवं भूमि के कब्जे के आधार पर हो गया। तब यह तय किया गया कि धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है एवं तहसीलदार ने नामान्तरण कर स्वीकार करने में कोई गलती नहीं की। (1993 RRD146 HC)
- 22- अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को किसी संस्था (इस मामले में सरकारी विद्यालय है) को दान करना अवैध एवं शून्य है। (1993 RRD593)
- 23- अधिनियम में दिनांक 11.11.92 से प्रावधान लुप्त हो जाने के कारण विधानसभा ने कृषि भूमि के हस्तांतरण करने में जो रुकावट थी, उसे समाप्त कर दिया है। इससे बदली हुई स्थिति में ऐसे अवैध हस्तांतरण से स्वीकृत नामान्तरण को निरस्त करने से कोई लाभ नहीं। (1994 RRD714)
- 24- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की भूमि को स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता चाहे वह दुरभि संधि डिक्री से ही हो, वह शून्य है। (1994 RRD270)
- 25- जो विक्रय धारा 42(क) के विरुद्ध किया गया है, वह प्रारंभ से ही शून्य है और इसलिए ऐसे विक्रय पत्र से हस्तांतरण नहीं होता। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण भी अवैध है एवं मानने योग्य नहीं है। (1994 RRD770)
- 26- अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को बैंक से लिये गये ऋण की बाकीयात को

नहीं चुकाने की वजह से नीलाम की गई। जिसको गैर अनुसूचित व्यक्ति द्वारा नीलामी में खरीदा गया। इससे धारा 42 (ख) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। (1995 RRD 52)

- 27- धारा 42 (ए) का उल्लंघन करते हुए खातेदार ने पंजीकृत विक्रय पत्र से एक बीघा 16 बिस्वा भूमि का विक्रय करते कब्जा दे दिया। नामान्तरकरण भी बिना खातेदार को नोटिस दिये तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार से किय गये विक्रय को धारा 42-ए के तहत विक्रय को सही करार दे दिया गया जिसके विरुद्ध खातेदार ने निगरानी पेश की। तय किया गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार की स्वीकृति की शहादत है, इसलिए खातेदार को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। उसने विक्रय पत्र के संबंध में किसी भी अदालत में आपत्ति या चुनौती नहीं दी। उसके उत्तराधिकारी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। न्यायालय ने कोई क्षेत्राधिकारिता की गलती नहीं की। (1996 RRD 73)
- 28- अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास विपरीत कब्जे व सहमति पर आधारित डिक्री अथवा बंटवारे से हस्तांतरित करने का आदेश गैर कानूनी है। (1998 RRD 607)



राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

1. Appeal/Decree/TA/5176/2002/Kota :

Sarju Rao s/o Patrao (deceased) through LRs:-

1. Ashok Rao s/o Sarju Rao.
2. Chandrakant s/o Sarju Rao.
3. Smt. Sindhu d/o Sarju Rao.
All rs/o Gaiwadi Kalkadevi Road, Mumbai.
4. Smt. Baby D/o Sarju Rao and w/o Pandurang r/o
Naigaon, Maharashtra.
5. Smt. Sunanda d/o Sarju Rao w/o Shashikant r/o
Sarav Pune.

.....Appellants.

VERSUS

1. Amritlal s/o Parmanand Khati r/o Ramganjmandi Tehsil
Ramganjmandi Distt. Kota.
2. State of Rajasthan through Tehsildar Ramganjmandi Distt. Kota.

.....Respondents.

Argued by :-

Shri Khadag Singh, counsel for the Appellants.

Shri Ashok Agarwal, counsel for the Respondent no. 1.

Shri V.P. Singh, Govt. Advocate for the State of Rajasthan.

2. Appeal/Decree/TA/5160/2004/Ganganagar :

Rami w/o Hariram (deceased) through LRs:-

1. Manoharlal
2. Rajender sons of late Shri Hari Ram
3. Sahabram

Suthar by caste r/o Mirjewala Tehsil and Distt.
Sri Ganganagar (Raj.)

.....Appellants.

VERSUS

1. Vidhya Devi w/o Lt. Krishanlal Caste Suthar r/o Mirjewala Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Raj.)
2. Khetaram
3. Rameshwarlal
4. Mahabeer Prasad
ss/o Lt. Krishanlal Minor through their mother and Natural Guardian Vidhya Devi w/o Lt. Krishanlal rs/o Mirjewala Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Raj.)
5. Rampratap
6. Phusaram
7. Om Prakash
8. Chetram
9. Ram Narayan
ss/o Arjanram Caste Suthar rs/o Mirjewala Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Raj.)
10. State of Rajasthan.

.....Respondents.

Argued by :-

Shri S.S. Meena, counsel for the Appellants.

Shri Manish Pandiya, counsel for the Respondent.

Shri V.P. Singh, Govt. Advocate for the State of Rajasthan

3. Appeal/Decree/TA/5161/2004/Ganganagar :

Rami w/o Hariram (deceased) through LRs:-

1. Manoharlal
2. Rajender sons of late Shri Hari Ram
3. Sahabram

Suthar by caste r/o Mirjewala Tehsil and Distt.
Sri Ganganagar (Raj.)

.....Appellants.

VERSUS

1. Rampratap
2. Phusaram
3. Om Prakash
4. Chetram
5. Ram Narayan

ss/o Arjanram Caste Suthar rs/o Mirjewala Tehsil and Distt.
Sri Ganganagar (Raj.)

6. Vidhya Devi w/o Lt. Krishanlal Caste Suthar r/o Mirjewala
Tehsil and Distt. Sri Ganganagar (Raj.)
7. Khetaram
8. Rameshwarlal
9. Mahabeer Prasad

ss/o Lt. Krishanlal Minor through their mother and Natural
Guardian Vidhya Devi w/o Lt. Krishanlal rs/o Mirjewala Tehsil
and Distt. Sri Ganganagar (Raj.)

10. State of Rajasthan.

.....Respondents.

Argued by :-

Shri S.S. Meena, counsel for the Appellants.

Shri Manish Pandeya, counsel for the Respondent.

Shri V.P. Singh, Govt. Advocate for the State of Rajasthan

4. Appeal/Decree/TA/2780/2009/Kota :

Ratna adopted son of Mathura Lal, s/o Chatra Caste Bairva r/o
Village Bambuliya Khurd Tehsil Piplda Distt. Kota.

.....Appellant.

VERSUS

1. Ramnath s/o Mathura Lal.
2. Heera Lal s/o Chatra
Bairva by caste rs/o Village Bambuliya Khurd Tehsil
Piplda Distt. Kota.
3. State of Rajasthan through Tehsildar Piplda Distt. Kota.
.....**Respondents.**

Argued by :-

Shri Ghanshyam Singh Lakhawat, counsel for the Appellant.

Shri Ashok Agarwal, counsel for the Respondent.

Shri Anil Sharma, counsel for the Respondent.

Shri V.P. Singh, Govt. Advocate for the Respondent.

Amicus Curiae :-

Shri O.L. Dave, Advocate

Shri Dunichand Didharia, Advocate

Shri P.S.Dashora, Advocate

Shri V.S. Rathore, Advocate

Shri Hemant Sogani, Advocate

Shri Jagdish Prasad Mathur, Advocate

Shri Hagami Lal Chaudhary, Advocate

Shri Brahmanand Sharma, Advocate

Shri S.P. Singh, Advocate

Shri Amrit Pal, Advocate

Shri Pushpender Naruka, Advocate

Shri Yogender Singh, Advocate

Shri Bhiyaram Chaudhary, Advocate

Shri Pradeep Vishnoi, Advocate

Shri R.P. Sharma, Advocate

Shri Rohit Soni, Advocate

Shri Vaibhav Pareek, Advocate

FULL BENCH

Shri V. Srinivas, Chairman

Shri Modu Dan Detha, Member

Shri Mohan Lal Nehra, Member

Shri Chiranji Lal Dayma, Member

Shri Rajinder Kumar, Member

J U D G M E N T

Dated : 30.8.2018

Per Shri Rajinder Kumar, Member :

Legal questions under consideration :-

1. This Full Bench was constituted to decide three Questions of Law, which had arisen in the course of final hearing of these second appeals. The said three questions are as under :-
 - i) Is the Full Bench decision reported at 2011 RRD page 508 applicable in cases where *khatedari* rights have been conferred under the Larger Bench decision in 1991 RRD page 1 but proceedings in appellate courts are pending ?
 - (ii) If so, can settled *khatedari* rights conferred in pursuance of 1991 RRD page 1 under Section 63 (iv) in cases where a *khatedar* tenant has been deprived of his possession and his rights to recover possession barred by limitation be deprived by the 2011 RRD page 508 judgment ?
 - (iii) What is the applicability of Section 183 RT Act in cases of permissive possession? When does a trespasser in permissive possession of any land turn into a trespasser liable for ejectment u/s 183 Rajasthan Tenancy Act, 1955 ?
2. We have heard learned counsels for the parties at length. Looking to the importance of aforesaid Questions of Law, as many as seventeen Advocates of this esteemed Bar appeared as *amicus-*

curiae and assisted this Full Bench by furnishing information, their expertise and valuable insights that have bearing on the issues involved herein.

Facts :-

3. Before dealing with the arguments advanced and our findings thereupon, it is *apposite* here to briefly narrate facts of the aforesaid Division Bench Appeals :-

(i) Appeal/Decree/TA/5176/2002/Kota :

4. In this case, the learned Trial Court of SDO Ramganj Mandi, District Kota passed a decree of declaration of *Khatedari* rights in favour of the plaintiff on the ground that he has become *khatedar* of the suit land by way of long, continuous, hostile and adverse possession. The name of the plaintiff-trespasser was also ordered to be incorporated in the Revenue Record by deleting the name of the original *khatedar*. The learned trial Court in arriving at the aforesaid conclusions placed reliance upon the law laid down in 1991 RRD 1 'Bagga versus Surender Singh' (hereinafter referred to as 'Bagga's case'). The first appeal of the original defendant-*khatedar* having been dismissed by the learned Revenue Appellate Authority, Kota, the second appeal was filed in this Board.

(ii) Appeal/Decree/TA/5160/2004/Ganganagar :

(iii) Appeal/Decree/TA/5161/2004/Ganganagar :

5. Two cross-suits no.214/94 and 138/96 [new number 200/2000] came to be filed in the Trial Court of SDO Sriganganagar in respect of the same land. First suit was filed by Smt. Rami Devi and others and the second one was filed by Rampratap and others. Both the suits were decided by the trial court vide common judgment dated 21.04.2003. The suit filed by Smt. Rami Devi and others was dismissed, whereas the suit filed by Rampratap and others was decreed on the ground that they had become *khatedars* of the suit land by way of adverse possession. In these two cases also, reliance was placed by the trial court upon Bagga's case. The first appeals filed by Smt. Rami Devi and others were dismissed by the learned Revenue Appellate Authority, Sriganganagar vide

judgment dated 16.10.2004. Hence, second appeals were preferred by them in this Board.

(iv) Appeal/Decree/TA/2780/2009/Kota :

6. The plaintiff Ramnath filed a suit for possession claiming himself to be the recorded *khatedar* of the suit land. The defendant contested the suit by filing counter-claim stating therein that the plaintiff has got his name entered in the revenue record in a secret manner, therefore, a prayer was made for substitution of his name in the revenue record by deleting the name of plaintiff. A further prayer for permanent injunction seeking to restrain the plaintiff from interfering into his peaceful possession over the suit land was also made. The trial Court vide judgment and decree dated 29.06.2007 dismissed the plaintiff's suit and decreed the counter-claim of the defendant in its entirety observing that the defendant has become *khatedar* of the suit land by adverse possession. In reaching the above conclusions, the trial Court placed reliance upon Bagga's case. Feeling aggrieved, the plaintiff approached the learned Revenue Appellate Authority, Kota by preferring first appeal, which was accepted on 24.02.2009 and the ejectment order was passed against defendant no.1. Hence, he preferred second appeal in this Board.

Arguments advanced are as under :

7. Shri Khadag Singh, Advocate has submitted that all the pending appeals and suits are required to be decided according to the ratio of case reported in 2011 RRD 508 'Jagdish and others Versus Sitaram and another' [hereinafter referred as Sitaram's case]. The judgments passed by the subordinate courts placing reliance on Bagga's case are required to be interfered with, as the said case did not lay down the correct legal position. The *khatedari* rights of trespassers must be revoked in those cases in which the appeals are pending. The cases in which the judgments of subordinate courts have attained finality are not required to be reopened.
8. Shri P.S. Dashora, Advocate has argued that the Rajasthan Tenancy Act, 1955 is a special statute. It only governs those matters for

which provisions are made therein. The *khatedari* rights can be acquired only under specific provisions made in the Act. The *khatedar* tenants have been given only hereditary and transferable rights. The proprietary rights nevertheless vest in the State Government. Relying upon a judgment of the Hon'ble Supreme Court in AIR 1963 S.C. 1077 'Patna Improvement Trust Versus Lakshmi Devi', the learned counsel has argued that the above Act directs the acquisition of *khatedari* rights in a particular way, therefore, it shall be deemed that it has prohibited its acquisition in any other way. Section 63 (iv) of the above Act provides that *khatedari* gets extinguished when a *khatedar* is deprived of possession over the agricultural land and his right to recover the same is barred by limitation. There is no provision in the Act for conferment of *khatedari* rights upon a trespasser of the said land. It is one thing to say that a *khatedar* who was in possession of the land at the time of dispossession had lost his rights but it is another thing to say that trespasser had become a tenant of the said land at the end of the prescribed period. The omission cannot be supplied by the courts, as the function of the courts is to interpret the laws and not to enact the laws. In this regard, the learned counsel has placed reliance on 1964 RLW 510 'Mst. Dhani Versus State.' He has also submitted that under section 88 of the Act, a right has been given to a person claiming himself to be a tenant or co-tenant to sue for declaration that he is a tenant or that he has share in such joint tenancy. This provision does not prescribe that a trespasser would also be entitled to the declaration of his rights upon the lands trespassed by him. He has further argued that the judgment in Bagga's case was passed on the strength of a judgment of the Hon'ble Madhya Pradesh High Court and the subsequent Full Bench of the Hon'ble Madhya Pradesh High Court has taken a contrary view in case reported in AIR 2001 M.P. 268 'State of Madhya Pradesh Versus Balveer Singh and ors.' Therefore, reliance on Bagga's case would be misconceived. Even otherwise, the law laid down in that case was against the basic provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, which postulate the welfare and benefit of the tenants. Thus, the irresistible conclusion is that

conferment of *khatedari* rights by illegal means of trespass is not permissible. In view of this, the law laid down in Sitaram's case must be made applicable to the pending appeals, despite the fact that *khatedari* rights have been conferred by the Subordinate courts pursuant to the decision given in Bagga's case. He has also argued that a Larger Bench of the Hon'ble Rajasthan High Court in 2015 (22) RBJ 486 'Tara Versus State of Rajasthan and others' has settled the controversy laying down that no person can acquire right by adverse possession in the lands, which are resumed or are in the tenancy of the tenants as *khatedars* thereof. In fact, the limitation prescribed in 3rd Schedule of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser is applicable and thus, the provisions of Section 27 of the Indian Limitation Act, 1963 are not applicable for claiming adverse possession over such lands. Learned counsel has also submitted that in a large number of latest decisions also it has been held that *khatedari* rights cannot be acquired by adverse possession. He has cited 2017 (2) RRT 1139 'Mansur and others Versus State of Rajasthan' decided by Hon'ble Rajasthan High Court and 2018 DNJ (Revenue) 59 'Amra Dangi and others Versus Bhera Meena and others' decided by this Board.

9. Shri Hemant Sogani, Advocate at the very outset has argued that the judgment of the Larger Bench rendered in Bagga's case was misleading. Most of the citations referred therein could not be found in the Law Journals. He further argued that Rajasthan's land scenario is governed by following Acts :-

- (i) The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952.

- (ii) The Rajasthan Land Tenancy Act, 1955.

- (iii) The Rajasthan Zamindar and Biswedari Abolition Act, 1959.

After the enforcement of above Acts, the intermediaries have been abolished. Now all the agricultural lands vest in the State Government. The *khatedars* have been given only hereditary and transferable rights, which do not include proprietary rights. A *khatedar* tenant pays rent to the State Government and thus, no

person can claim rights by adverse possession against a tenant. He further argued that the provisions of Section 27 of the Indian Limitation Act, 1963 do not apply to the Rajasthan Tenancy Act, 1955, as this Act itself provides for filing a suit for possession against the trespasser. Even otherwise, Section 27 of the Indian Limitation Act, 1963 is regarding the extinguishment of rights and not regarding the conferment of rights upon a trespasser. Relying upon the judgment of Hon'ble Supreme Court reported in 1994 (5) SCC 562 'Md. Noor and ors Vs Md. Ibrahim and ors', the learned counsel argued that though tenancy rights are heritable and transferable yet they are not sufficient to constitute full ownership in a tenant. He further argued that adverse possession can be claimed against a true owner and not against a tenant. There are specific provisions in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for conferment of *khatedari* rights under sections 12(2), 13, 15, 15 AAA, 15B and 19 and the acquisition of *khatedari* rights by adverse possession is not provided therein. There is no provision in the 3rd Schedule of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 enabling a trespasser to file suit on the basis of adverse possession. He further argued that the Rajasthan Tenancy Act, 1955 prohibits sub-letting and trespassing over the agricultural lands, therefore, providing *khatedari* rights by adverse possession would run contrary to the basic tenets of this Act. As the judgment was passed in Bagga's case without considering the relevant legal position, therefore, relief cannot be granted to the trespassers in pending suits and appeals on the strength of law laid down in that judgment. He further argued that the duty of the courts is to declare rights of the litigants on the basis of the prevailing laws and the courts cannot confer rights upon them. Neither any rights were conferred nor any rights have been taken away by this Board in the Larger Bench and Full Bench decisions respectively. If the Rajasthan Tenancy Act, 1955 is interpreted, the logical conclusion is that conferment of *khatedari* rights by way of adverse possession is expressly and impliedly barred. His further argument is that though this Full Bench has not been constituted to examine the correctness or otherwise of the law laid down by earlier Full Bench of this Board in Sitaram's case

(supra) yet this Full Bench is required to look into and examine the points raised before it in that regard. The cases which have already attained finality are not required to be re-opened. But the pending suits and appeals are required to be decided on the basis of law laid down in Sitaram's case.

10. Shri O.L. Dave, Advocate has argued that *khatedari* rights cannot be acquired by adverse possession. The law laid down in Bagga's case was not a good law.
11. S/Shri Jagdish Prasad Mathur and Bhiya Ram Choudhary have supported all the aforesaid arguments.
12. Shri Amrit Pal, Advocate has argued that 'adverse possession' and 'permissive possession' are two sides of the same coin. No *khatedari* rights can be conferred on the basis of adverse possession. Otherwise, there will be instances of evasion of stamp duty. The tenants would indulge in entering collusive arrangements of letting their *khatedari* rights extinguished and conferring the same upon the trespassers by way of adverse possession. Therefore, the law laid down in Sitaram's case must prevail in the pending suits and appeals.
13. Shri Hagami Lal, Advocate has also endorsed the arguments of Shri Dashora and Shri Hemant Songani Advocates. He has also submitted that in view of the provisions contained in Section 59 to 62 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, a trespasser is not entitled to retain agricultural holdings.
14. Shri Dunichand Didharia, Advocate has argued that the entire controversy can be resolved on a literal interpretation of section 60 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. According to this provision, a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighborhood does not lose his interest in the holding, if he leaves in-charge thereof a person responsible for payment of land revenue and gives written notice to the land-holder regarding such arrangement. If the person so left in-charge is a person on whom, in the event of the tenant's death, the tenant's interest would devolve, or who is to manage the holding for the benefit of the person on whom, in the event of the tenant's death, the tenant's interest would devolve, the tenant shall

on expiry of a period of seven years lose his interest in his holding unless he, within such period, resumes cultivation thereof and such interest shall devolve on the person on whom the tenant's interest would devolve in the event of his death. If the person so left in-charge is not a person mentioned above, the tenant shall on the expiry of the period for which he could have sub-let, be presumed to have abandoned his holding unless within such period he resumes its cultivation. Section 60 (4) provides that a tenant who ceases to cultivate and leaves the neighborhood otherwise than in accordance with the provisions of sub-section (1), shall be presumed to have abandoned his holding. According to Shri Didharia, it is clear from these provisions that if a tenant does not take care of his lands and another person trespasses upon the same, it would be a case of abandonment and the land would automatically vest in the State Government. As a matter of fact, the acquisition of *khatedari* rights by way of adverse possession is barred by law in specific terms. Written submissions to buttress the oral arguments were also filed by Shri Didharia, Advocate.

15. Shri Vaibhav Pareek, Advocate has argued that the plea of adverse possession cannot be raised by a tenant against the true owner of the land.
16. Shri Pushpendra Naruka, Advocate has argued that a wrong notion has developed that if *khatedari* rights are not conferred upon trespassers, a situation of lawlessness would arise. On the contrary, the conferment of *khatedari* rights on trespassers would amount to granting licence to the wrong-doers.
17. Shri R.P. Sharma, Advocate has submitted that the law laid down in Bagga's case was bad law. The correct legal position has been laid down in Sitaram's case, which must prevail in pending appeals. In this regard, he has relied upon 1998 DNJ (SC) 41 'General Manager Telecom Versus S. Srinivasan Rao and others.' He has further argued that the State Government must acquire the lands upon which the rights have been illegally acquired by trespassers on the plea of adverse possession. In this regard, a request may be made to the State Government for doing the needful.

18. Shri Yoginder Singh, Advocate has argued that in pending appeals, the law laid down in Sitaram's case must prevail. However, the cases which have attained finality are not required to be re-opened.
19. Shri V.P. Singh, learned Government Advocate has argued that the courts cannot promulgate the law. They have to interpret the existing laws. Since an appeal is a continuation of suit, all the pending appeals are required to be disposed of in accordance with the law laid down in Sitaram's case. The definition of the word "tenant" given in Section 5 (43) excludes a trespasser.
20. Shri Virender Singh, Advocate has argued that the judgments of the courts cannot be read as statutes, as they do not create rights. They merely declare the rights of litigants. Relying upon 2011 (2) RRT 834 'Chatti Konati Rao and others Versus Palle Venkata Subba Rao', the learned counsel has argued that in order to constitute adverse possession, the possession must be expressly or impliedly in denial of title of the true owner in a peaceful, continuous and open manner. A person pleading adverse possession has no equities in his favor, as his intention is to defeat the rights of true owner. Therefore, no protection is required to be given to the trespassers.
21. Shri G.S. Lakhawat, Advocate has also argued that there is no provision in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 conferring *khatedari* rights on a trespasser. It is not the duty of the court to enlarge the scope of the legislation or the intention of the legislature when the language of the provision is plain and unambiguous. The courts must decide what the law is and not what it ought to be. As the law laid down in Bagga's case was passed by the Board exceeding its jurisdiction, no reliance can be placed on it. The pending appeals are required to be dealt with as per the law laid down in Sitaram's case. To buttress his arguments, the learned counsel has placed reliance on AIR 2010 S.C. 2771 'Satheedevi Versus Prasanna', AIR 1992 S.C. 96 'Union of India Versus Deoki Nandan,' and AIR 1965 Rajasthan 70 'Mst. Dhani Versus State and anr'.
22. Shri Brahmanand Sharma, Advocate argued that the law must not support a person who takes possession of the property of the true

- owner in a clandestine manner. He placed reliance on 2008 (2) RLW 1101 'Hemaji Waghaji Jat Vs Bhikhabhai K. Harijan & ors'.
23. *Per Contra*, Shri Ashok Agarwal, Advocate argued that the law laid down in Bagga's case is a good law on the subject of adverse possession. All the relevant aspects were taken care of while passing the said judgment. On the other hand, the law laid down in Sitaram's case is not good law, as it consists of a number of discrepancies in it. According to the learned counsel, the said judgment was passed by the Full Bench only for the sake of doing something new. One of the discrepancies in the Full Bench judgment is regarding the scope of section 63 and 183 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Though there are specific provisions in the said Act for conferment of *khatedari* rights upon the tenants yet there is no bar in the Act for acquiring the *khatedari* rights by way of adverse possession. The law laid down by Hon'ble Rajasthan High Court in Tara Vs State of Rajasthan is regarding deity lands and it has nothing to do with conferment of *khatedari* rights upon trespassers by way of adverse possession. If the *khatedari* is not given to the persons holding settled possession, in whom the *khatedari* rights would vest? This question remains undecided, if the law laid down in Sitaram's case is allowed to prevail. Therefore, the law laid down in Bagga's case must prevail. In support of his submissions, he has relied upon 2003 (1) WLC 349 (civil) 'Sarwan Kumar & ans Versus Madan Lal Aggarwal.'
24. Shri Pradeep Vishnoi, Advocate has argued that the applicability of Section 27 of the Limitation Act, 1963 is not excluded by Section 204 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. This section itself says that it is applicable subject to the provisions of the Limitation Act. Even otherwise, a *khatedar*-tenant under the scheme of the above Act has hereditary as well as transferable rights in the agricultural holdings. At times, when the said lands are acquired by the State Government for various purposes, it is duty bound to pay compensation to the concerned *khatedars*-tenants. Therefore, full ownership over the agricultural land vests in *khatedars*. The State Government has very limited rights of collection of land revenue

from them. In this way, there is no bar in conferring *khatedari* rights upon the trespasser, who is in settled possession over the said land. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 does not, impliedly or expressly, state that *khatedari* rights will not be conferred upon the trespasser by way of adverse possession. Had the State Government been the full owner of the agricultural lands, there would have been a specific clause in 3rd Schedule of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 enabling the State Government also to file a suit against the trespasser for recovery of possession of the land. He has further argued that if a person in settled possession is denied *khatedari* rights on the basis of adverse possession, how and from whom the land revenue would be recovered? This question has neither been examined in Bagga's case (supra) nor in Sita Ram's case. Therefore, both the above judgments do not lay down correct law and re-look on all the aspects is the need of the hour. He has further argued that a person in possession of the land is not getting *khatedari* rights in pursuance to the judgment passed in Sitaram's case, whereas right to property is the constitutional right of every citizen under Article 311 of the Indian Constitution. As *khatedari* rights are being denied to him, a multiplicity of litigation takes place. A situation of lawlessness has been created due to non-conferment of *khatedari* rights to such persons. On the other hand, it has amounted to windfall for the Advocates. He has also argued that the word "Adverse Possession" is not defined by any statute. The only provisions regarding adverse possession are contained in Limitation Statutes. These provisions extinguish the right to sue, as after the stipulated period of 12 years, the right of *khatedar* to sue extinguishes. In such circumstances, the only recourse which would become available to the State Government is to file a suit for recovery of possession but in the absence of an enabling provision in this regard in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the State Government would not be able to file such a suit as well. The only provision in this regard is contained in section 175 of the Tenancy Act, 1955 and that too, only in case of violation of section 42 of the said Act. Therefore, to strengthen the administration of justice,

there is an urgent need for enactment of specific laws on the subject protecting the rights of persons in settled possession.

25. Shri Rohit Soni, Advocate has supported the arguments advanced by Shri Pradeep Vishnoi, Advocate.
26. Shri S.P. Singh, Advocate has also supported the arguments advanced by Shri Ashok Agarwal and Shri Pradeep Vishnoi Advocates. In addition, he has submitted that there is no provision in the Act for conferment of *khatedari* rights on a person in settled possession after the extinguishment of *khatedari* of original *khatedar* by lapse of time. Therefore, the legislature must fill the gaps by making the desired amendments in the land laws.
27. Shri Manish Pandiya, Advocate has submitted that the laid down in Sitaram's case is not a good law.
28. We have pondered over the rival arguments and perused the record carefully. We have also respectfully studied the law laid down in the above citations.
29. At the outset, it is noticeable that this controversy had arisen on account of the fact that a Larger Bench of this Board in Bagga's case has held that by adverse possession, a trespasser acquires *khatedari* rights, provided that the same is not prohibited by sections 16 and 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. A large number of suits and appeals were decided by the trial courts and first appellate courts placing reliance on the judgment of Larger Bench. In this Board also, considerable number of second appeals are pending against the said judgments and decrees. However, in the meantime, a Full Bench of this Board in 2011 RRD 508 'Jagdish and others Versus Sitaram and other' specifically overruled the judgment of the Larger Bench. Therefore, a question arose as to the applicability of Sitaram's case in the appeals, which had arisen against the judgments and decrees rendered on the basis of law laid down in Bagga's case. Therefore, first of all, it would be necessary here to discuss the findings of the aforesaid Larger Bench and Full Bench of this Board regarding the law of adverse possession.

Findings of the Larger Bench in Bagga's case :

30. On 15th October, 1990, a Larger Bench of this Board in above case held as under :-

"A suit can be filed under Section 84 Rajasthan Tenancy Act for the declaration of Khatedari Rights on the basis of adverse possession. The view taken in 1990 RRD 212 is erroneous. The view taken in 1977 RRD 479 and 1985 RRD 567 is also not entirely correct. The correct law is that by adverse possession the trespasser acquires khatedari rights provided that the acquisition of khatedari rights is not specifically prohibited by law, e.g., Section 42 and Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act."

Reasoning :-

31. Following reasons were assigned by the Larger Bench in arriving at the said conclusions :

- (i) After conferment of 'Khatedari' upon a tenant, he gets right to retain possession over the land and cultivate the same subject to certain conditions. If any of the conditions are violated, the land may be resumed by the State Government. In nutshell, the State Government remains land-owner, even after conferment of khatedari rights upon a tenant.
- (ii) Though the Rajasthan Tenancy Act, 1955 is a special law yet the provisions of the Indian Limitation Act, 1963 would apply to the Revenue Tenancy matters. Section 214 (3) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 shows that the general law of limitation is applicable to proceedings under the tenancy law subject to provisions contained in sub-Section (1) and (2) of Section 214.
- (iii) As a matter of fact, the applicability of Section 27 of the Limitation Act, 1963 is not excluded and khatedari rights may be acquired by adverse possession against the khatedar but not against the State Government. Thus, the State Government will not be bound by such a decree.

The learned Larger Bench in its aforesaid judgment quoted with

approval a paragraph from the book "Law of Adverse Possession" written by the eminent author Shri M. Krishna Swamy. For the sake of clarity, the said paragraph is being reproduced here, as it has been quoted in the judgment of the Larger Bench itself:-

"Adverse possession against the tenant is not generally adverse against the landlord during the continuance of the lease. The reason is that so long as the tenancy continues, the landlord has no immediate right of possession, and, therefore, can have no right to sue for possession. It is true that he can, during the continuance of the tenancy, bring a suit for declaration, but the granting of a decree for declaration is, in the discretion of the court, and the landlord is not bound to bring a suit for such a declaration, unless a right to sue for possession of the land accrues to him. There may be cases where the lessee's right to actual possession against the trespasser would be barred, while the right of the lessor would remain unaffected as long as the lease continues. So long as the lease continues, time does not run in favour of a third person who has dispossessed the lessee, for the lessor has no immediate right of possession. The fact that a stranger ousts the lessee and obtains possession during the pendency of the lease does not accelerate the lessor's right to possession, in other words, the stranger's possession may be adverse to the lessee without being adverse to the lessor, the rule being that a tenant cannot bind the reversioner either by his positive act or by neglect, and accordingly, even if the lessee is dispossessed, time does not run in the trespasser's favour except from the expiration of the term. The possession of a trespasser, during the continuance of a lease does not become adverse against the lessor who is in possession by receipt of rent from his lessee, and so long as such rent is not intercepted by a trespasser, the lessor cannot be said to have been dispossessed. It is the lessee's duty to recover possession from the trespasser."

The learned Larger Bench was of the considered opinion that controversy raised before it was squarely covered by the above opinion of learned author Shri M. Krishna Swamy. However, the context in which the said opinion was rendered by the esteemed

author is not mentioned in the judgment of the Larger Bench. No doubt that the "Digests and Commentaries" of the esteemed authors do occupy very important place in understanding the legal propositions. However, generally they contain a synthesis of the various legal works and thus, the context in which an opinion has been rendered by an author must be known before making reliance upon the same. In addition to it, the learned Larger Bench also relied upon a judgment of the Hon'ble Madhya Pradesh High Court reported in AIR 1980 M.P. 183 'Kashiram Vs Nathu', wherein it was held that a person may acquire rights of a "Bhuswami" by adverse possession qua that "Bhuswami" but whether he acquires any right in that land qua the State Government would depend upon the question whether the acquisition of the right by adverse possession is lawful or not. In view of these reasons, the Larger Bench repelled the contention that tenancy rights can only be acquired under Section 13, 15 and 19 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and in no any other manner. However, in a subsequent judgment given by Full Bench of Hon'ble Madhya Pradesh High Court reported in AIR 2001 M.P. 268 'State of M.P. Vs. Balveer Singh', it was held that no mode other than the modes provided for conferment, acquisition or accrual of "Bhuswami" right in the special statute can be created or presumed to exist so as to entitle even a trespasser to become a tenant by way of adverse possession. In view of above, both the factors upon which the Larger Bench decision was based fall on the ground. It is also pertinent that the Larger Bench did not consider in its judgment that under the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there are only specific modes of acquiring the *khatedari* rights, which are contained in Sections 13, 15, 15AAA and 19 and the conferment of *khatedari* rights by way of adverse possession is not provided in any of the said provisions. This fact was also not considered by the Larger Bench that the Rajasthan Tenancy Act, 1955 is a Special Act and the provisions contained in Section 27 of the Limitation Act, 1963 do not apply for claiming adverse possession on agricultural holdings. Therefore, this judgment was passed by the Larger Bench by ignoring the legal provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Findings of the Full Bench in Sitaram's case :

32. As noticed earlier, the Revenue Courts of the State followed the dictum of Bagga's case in a considerable number of cases, thereby, conferring *khatedari* rights upon the trespassers by way of adverse possession, until the validity of the said judgment came to be examined by a Full Bench of this Board in 2011 RRD 508 'Jagdish and ors Vs Sitaram and another.' The earlier Full Bench of this Board in Sitaram's case (supra) also consisted of a total number of five Members, including the Chairman. After examining the matter at length, which included the scope of the provisions conferring *khatedari* rights mentioned in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the Full Bench held as under :
 - (i) The Larger Bench in its judgment in Bagga's case has not laid down a correct law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor.
 - (ii) The extinguishment of tenancy rights does not create *khatedari* in the trespasser on the basis of adverse possession.
 - (iii) The Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of *khatedari* rights.
 - iv) The judgment of Larger Bench rendered in Bagga Vs. Surendra Singh reported in 1991 RRD Page 1 is not a good law and thus, the same deserves to be set aside.
33. It is revealed from above that after overruling of the law laid down in Bagga's case, the doctrine of *stare decisis* comes into play. The courts cite to *stare decisis* when an issue has previously been brought before the court and ruling already issued. This doctrine of *stare decisis* operates both horizontally and vertically. A horizontal *stare decisis* is one where a court adheres to its own precedent. A vertical *stare decisis* is one when a court applies a precedent from a higher court. The importance of *stare decisis* was summarised by Hon'ble Supreme Court in AIR 1975 SC 907, 'Mamleshwar Prasad Vs Kanahaiya Lal' in the following terms :

"Certainty of the law, consistency of rulings and comity of courts - all flowering from the same principle - converge to the conclusion that a decision once rendered must later bind like cases."

Therefore, the revenue courts and this Board are bound by the law laid down in Sitaram's case.

34. It is pertinent that the above view of the Full Bench of this Board that the principle of law relating to adverse possession is not applicable to the *khatedari* lands finds favor with a Full Bench judgment of the Hon'ble Rajasthan High Court in 2015 (22) RBJ 487 'Tara Vs State of Rajasthan', where in it was held as under:-

"35. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides the limitation for bringing an action for dispossession and thus, the principle of law relating to adverse possession and the action to be brought within the period specified in Section 27 of the Limitation Act will not apply to the khatedars under the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

36. We, therefore, decide the question No. (iv) in favor of the State and hold that no person can acquire right by adverse possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as khatedars. The Limitation applicable under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for filing suit for possession against the trespasser will be applicable. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 being a Special Act, will prevail and the provisions of Section 27 of the Limitation Act will not apply for claiming adverse possession on such lands."

Thereafter also, in a catena of cases, the Hon'ble Rajasthan High Court has held that suit on the basis of adverse possession is not maintainable in respect of the agricultural holdings as there is no provision in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 for conferring *khatedari* rights by way of adverse possession. To quote a few of such decisions, reliance can be placed on 2017 (2) RRT 1139 'Mansur and others Vs State'; and 2018 (1) RRT 175 'Chittar and others Vs Smt. Bhanwari Devi and ors.' In 2017(3) DNJ (Raj.) 1340 'Shriya Vs Gram Panchayat Ranoli, the Hon'ble Rajasthan

High Court has held that a suit cannot be maintained on the basis of adverse possession. Merely having adverse possession does not entitle the plaintiff to claim ownership over the property. The plea of adverse possession can be taken as a measure of defense and can only be used as a shield and not as a sword.

35. There is equally a considerable force in the argument that though tenancy rights are heritable and transferable yet they are not sufficient to constitute full ownership in a tenant. In this context, the following observations of Hon'ble Supreme Court in Mohd. Noor's case (supra) are relevant:-

"4. To determine this it is necessary to examine the nature of khatedari rights and if a transfer of such right amounts to transfer of ownership. A khatedar tenant is one of the tenants mentioned in clause (a) of Section 14 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (hereinafter referred to as 'the Tenancy Act') and clause (c) defines the circumstances in which a person may become a khatedar tenant. Such a tenant has a right to bequeath his interest under Section 59 of the Tenancy Act and transfer his interest under Section 41 of the same Act on conditions specified in Section 42 and 43. His interest is heritable under Section 40 as well. Is that sufficient in law to make him owner of the property? Is the transfer made by a khatedar tenant a transfer of ownership? A khatedar tenant, admittedly is a person by whom rent is payable under Section 43 of the Tenancy Act. The effect of it in law is that such a person cannot be deemed to be an absolute or unlimited owner....

5.Heritability and transferability are no doubt some of the many and may be most important ingredients of ownership. But they by themselves cannot be considered as sufficient for clothing a person with absolute ownership. Their absence may establish lack of ownership but their presence by itself is not sufficient to establish it. The ownership concept does not accord with the status of a person who is paying the rent.

It is true that after abolition of Zamindari in various States the tiller of the soil has become owner of the land. But it cannot be disputed that the proprietorship of the land vests in the State to whom the rent is payable. It is not uncommon that a person in possession of an agricultural holding even as an owner cannot put his land to any use he desires. For instance, if the land has to be converted from agricultural use to non-agricultural use then the tenure holder is required to obtain permission of the State Government or the appropriate authority appointed by it. All these indicate that even though a khatedar tenant is an owner for all practical purposes but his ownership is limited."

The above observation of the Hon'ble Supreme Court are also complete answers to the arguments raised before us that after enactment of the various land laws post-independence, the true owner of agricultural holdings is the State Government and the *khatedars* have limited ownership therein. As a matter of fact, the relinquishment of possession by a tenant does not enure to the benefit of a trespasser against the true owner so as to accept his claim for adverse possession. [2011 (1) RRT 575 'Chatti Konati Rao and anr Vs Palle Venkata Subba Rao']

36. From the discussion that precedes, it follows that *khatedari* rights cannot be acquired through adverse possession under the scheme of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.
37. Now, we will take up the legal questions posed before us for our decision.

Re.: Question No. (i)

38. To put it very clear, here we have to decide which of the two decisions [1991 RRD 1 or 2011 RRD 508] would apply to the pending appeals, where '*khatedari*' has been conferred by the subordinate courts on the basis of adverse possession.
39. This question can be decided in following three different ways and the outcome would be the same :-

(i) **Appeal is a continuation of suit :**

40. It is fairly well settled principle of law that a right of appeal is a substantive right and is creature of a statute. Sections 222 to 228 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 provide for filing of appeals. Section 222 is the main controlling provision on the right of appeal in relation to any decree or order passed by the revenue courts of the State. It clearly bars the filing of appeal, if not provided by the Act.
41. The use of the words "an appeal shall be ..." in the above sections reinforces our view that right of appeal is a vested right of the litigant. Strictly speaking, an appeal is one in which the question is, whether the judgment or order of the subordinate court from which the appeal has emanated was lawful on the materials laid before that court. In AIR 1965 S.C. 1585 'State of Kerala versus K.M. Charia Abdulla & Co.', it was held that an appeal is a continuation of the proceedings, as the entire proceedings are before the appellate court and it has the power to review the evidence subject to the prescribed statutory limitations. In AIR 1963 S.C. 698 'Hari Shankar versus Rao Girdhari Lal', it was held that a right of appeal carries with it right of re-hearing on law as well as fact. In SLP No. 236/06 (decided on 15.12.2006) 'Kamla Devi versus Khushal', it was held by the Hon'ble Supreme Court that an appeal, as is well known, is the right of entering a Superior Court invoking aid and interposition to redress an error of the court below. The central idea behind the filing of an appeal revolves around the right as contra-distinguished from the procedure laid down therefor. As a matter of fact, the legality of a judgment or order is also examined in appeal, which is a stage of the suit itself. Therefore, the appellate courts may, with a view to mould the relief, take into consideration subsequent events, including the latest legal position as well.

(ii) **By giving retrospective effect to the earlier decision :**

42. A part from it, whenever a decision is overruled by a larger bench, the previous decision is completely wiped out and the courts would have to decide the cases according to law laid down

by the latest decision and not by the decision which has been expressly over-ruled. For this legal preposition, there is an authoritative pronouncement of the Hon'ble Supreme Court reported in AIR 1980 S.C. 126 'Ramdas Bhikaji Chaudhary versus Sadanand and others'. Judicial propriety also requires the appellate courts to follow the Full Bench decision. In reaching these conclusions, we can rely upon the *ratio decidendi* of S. Srinivasan Rao's case (supra).

43. In Tara Versus State of Rajasthan and others (supra), a Larger Bench of the Hon'ble Rajasthan High Court has directed the Revenue Authorities in the State to consider and decide the matters pending before them in accordance with the answers given by the Hon'ble High Court to the questions framed. On this premise also, the latest law shall prevail over the pending suits and appeals. In Mst. Dhani Versus State (supra) also, the Hon'ble Rajasthan High Court has held that there is no bar in giving retrospective effect to the decisions of Higher Courts.
44. In view of above, the judgment passed in Sitaram's case would be applicable to the pending appeals.

(iii) On the basis of doctrine of *per-incuriam* :

45. As is evident from the preceding discussion, the judgment in Bagga's case was given by the Larger Bench in ignorance of the terms of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Sir John Salmond in his 'Treatise on Jurisprudence' aptly remarked the circumstances under which a precedent can be treated as '*per incuriam*'. One of the said circumstances is if it was rendered in ignorance of a statute or rule having the force of law.
46. To our mind, if a court knew of the existence of a particular provision and yet does not appreciate its relevance to the matter in hand, such a judgment would stand vitiated being *per incuria*. Thus, the judgment given by the Larger Bench in Bagga's case was *per incuriam*, as the vital provisions were ignored therein.
47. Therefore, we conclude by saying that in the pending appeals, the appellate courts are required to take into account and give effect to

the law laid down by Full Bench of this Board in Sitaram's case, notwithstanding the fact that *khatedari* rights have been conferred by the Subordinate Courts under the Larger Bench decision in Bagga's case.

Re.: Question No. (ii)

48. There is no dispute that normally the courts do not possess power and jurisdiction to re-open the cases, which have attained finality merely because a contrary view in a subsequent judgment has been taken by the Larger Bench or the Full Bench. In Sarwan Kumar's case (supra), it was held by Hon'ble Supreme Court that doctrine of prospective overruling is saved to the cases which have attained finality. Therefore, the cases which have attained finality are not liable to be re-opened, even though a *khatedar* has been deprived of his *khatedari* rights in pursuance to the decision given in Bagga's case and his right to recover possession stands barred by limitation as well, and in such cases, the law laid down in Sitaram's case would not come to rescue such a *khatedar* tenant.

Re.: Question No. (iii)

49. The third question of law may be divided into following two parts :-
- (a) What is the applicability of section 183 Rajasthan Tenancy Act, 1955 in cases of permissive possession?
 - (b) When does a person in permissive possession of any land turn into a trespasser liable for ejectment under section 183 Rajasthan Tenancy Act, 1955?
50. The answers to above questions would largely depend upon the definition of the word 'trespasser' given in section 5(44) of the above Act, which is as under:

"44. Trespasser shall mean a person who takes or retains possession of land without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him."

The above definition may be analysed in the manner that a trespasser is :-

- (a) a person who takes possession of land without authority. It would mean and convey a wrongful entry upon the land of another.
- (b) a person who retains possession without authority. It would mean and convey the entry of a person to be lawful but becoming unlawful after the expiry of contractual period.
- (c) a person who prevents another person from occupying land duly let out to him.

Thus, a person in permissive possession of a land will be covered under second category and that too only if he retains the possession without authority. So long as his possession is within authority, he cannot be termed as a trespasser.

51. At this stage, it would be relevant to mention the provisions contained in section 183 of the above Act, which pertain to ejectment of certain trespassers :-

"183. Ejectment of certain trespasser - (1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year, during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956."

52. Thus, it becomes clear that so long as the possession of a person in permissive possession is within authority, the provisions of section 183 of the Rajasthan Tenancy Act would not get attracted for evicting him from that land. In AIR 1971 Orissa 195 Bhabagrahi Misra Vs. Mangovinda Moharana, it was held that when

possession commences in a permissive character, it does not become adverse unless by some positive overt act, it is indicated that such possession became adverse either in the hands of the successor or even in the hands of original permissive occupant.

53. In 1994 (6) SCC 591 'Thakur Kishan Singh Vs. Arvind Kumar', it was held as under :-

"A possession of a co-owner or of a licensee or of an agent or a permissive possession to become adverse must be established by cogent and convincing evidence to show hostile animus and possession adverse to the knowledge of real owner. Mere possession for howsoever length of time does not result in converting the permissible possession into adverse possession."

54. In AIR 1996 SC 910 'Mohan Lal Vs. Mirza Abdul Gaffar', it was held as under :-

"...Having come into possession under the agreement, he must disclaim his right thereunder and plead and prove assertion of his independent hostile adverse possession to the knowledge of the transferor or his successor in title or interest and that the latter had acquiesced to his illegal possession during the entire period of 12 years i.e. upto completing the period of his title by prescription nec vi nec clam nec precario. Since the appellants' claim is founded on section 53-A, it goes without saying that he admits by implication that he came into possession of the land lawfully under the agreement and continued to remain in possession till date of the suit. Thereby, the plea of adverse possession is not available to the appellant."

55. In 2000 WLC (SC) 240 'Roop Singh Vs. Ram Singh', it was observed by the Hon'ble Supreme Court as under :

"Once it is admitted by implication that plaintiff came into possession of the land lawfully under the agreement and continued to remain in possession till the date of the suit, the plea of adverse possession would not be available to the

defendant unless it has been asserted and pointed out hostile animus of retaining possession as an owner after getting in possession of the land"

56. In 2016 (1) RRT 205 'Mohan Lal Vs. Chenram & ors.', it was held by this Board that a suit cannot be decreed on the basis of adverse possession, if the plea of permissive possession is taken.
57. It becomes clear from the above judgments that as soon as the person in permissive possession starts asserting his open, adverse and hostile title to the knowledge of the *khatedar* tenant, a cause of action accrues to the *khatedar* tenant to sue the trespasser for ejectment from that land. It is the intention to claim exclusive title, which makes possession adverse and this *animus possidendi* must be evidenced and effectuated by the manner of occupancy of the said land. Though, no question of adverse possession or of limitation arises when the possession of a person has continued under the lease or other agreement, however, if the person in possession starts asserting an adverse title against the *khatedar* tenant and repudiates the agreement, he loses his right to retain the land.
58. Hence, question no. 3 is answered in the following terms :-
Section 183 of the Rajasthan Tenancy Act is not applicable in the cases of permissive possession. A person in permissive possession of any land turns into a trespasser liable for ejectment under section 183 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 only when he starts asserting his open, adverse and hostile title to the knowledge of the *khatedar* tenant.

A request to the State Government :

59. Having answered the questions of law referred to this Full Bench, it is pertinent here to mention that In 2008 (2) RLW (SC) Civil 1101 'Hemaji Waghaji Jat Vs. Bhikhabhai Khengarbhai & ors.', the Hon'ble Supreme Court observed that the law of adverse possession is irrational, illogical and wholly disproportionate. It is also extremely harsh for the true owner and a windfall for a dishonest person. The law ought not to benefit a person who in a

clandestine manner takes possession of the property of the owner in contravention of law. The Hon'ble Supreme Court further observed that this in substance would mean that this law gives seal of approval to the illegal action or activities of a rank trespasser or who had wrongfully taken possession of the property of the true owner. In such circumstances, the Hon'ble Supreme Court observed that there is an urgent need of fresh look regarding the law of adverse possession. Therefore, a recommendation was made to the Union of India to seriously consider and make suitable changes in the law of adverse possession. A copy of that judgment was ordered to be sent to the Secretary, Ministry of Law and Justice for taking appropriate steps in accordance with law. In 2012 (2) RRT 904 'State of Haryana Vs. Mukesh Kumar & ors.', the Hon'ble Supreme Court observed that the concept of adverse possession was born in England in 1275 A.D. and it was subsequently adopted in the United States. We have inherited this law of adverse possession from the British. The Parliament may consider abolishing the law of adverse possession or at least amending and making substantial changes in law in the larger public interest. The Parliament must consider at least to abolish "bad faith" adverse possession i.e. adverse possession achieved through intentional trespassing.

60. After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the *khatedari* rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. It is creating a lot of chaos and confusion among the litigants as well as the administrative machinery. This omission in the land laws has also become a cause of multiplicity of litigation. Therefore, we would like to recommend the State of Rajasthan through Chief Secretary for making suitable changes in the land laws of the State so as to abolish the law of adverse possession in its entirety and in the alternate to make a clarification for vesting of *khatedari* rights of the lands, which have been acquired through adverse possession.

61. The answers to the questions referred for our decision are being thus summarized as under:-

Question No. (i) :-

Is the Full Bench decision reported at 2011 RRD page 508 applicable in cases where *khatedari* rights have been conferred under the Larger Bench decision in 1991 RRD page 1 but proceedings in appellate courts are pending ?

Answer :-

In the pending appeals, the appellate courts are required to take into account and give effect to the law laid down by Full Bench of this Board in Sitaram's case, notwithstanding the fact that *khatedari* rights have been conferred by the Subordinate Courts under the Larger Bench judgment rendered in Bagga's Case.

Question No. (ii) :-

If so, can settled *khatedari* rights conferred in pursuance of 1991 RRD page 1 under Section 63 (iv) in cases where a *khatedar* tenant has been deprived of his possession and his rights to recover possession barred by limitation be deprived by the 2011 RRD page 508 judgment ?

Answer :-

The cases which have attained finality are not liable to be re-opened, even though a *khatedar* has been deprived of his *khatedari* rights in pursuance to the decision given in Bagga's case and his right to recover possession stands barred by limitation as well, and in such cases, the law laid down in Sitaram's case would not come to rescue such a *khatedar* tenant.

Question No. (iii) :-

What is the applicability of Section 183 RT Act in cases of permissive possession? When does a trespasser in permissive possession of any land turn into a trespasser liable for ejectment u/s 183 Rajasthan Tenancy Act, 1955?

Answer :-

Section 183 of the Rajasthan Tenancy Act is not applicable in the cases of permissive possession. A person in permissive possession of any land turns into a trespasser liable for ejection under section 183 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 only when he starts asserting his open, adverse and hostile title to the knowledge of the *khatedar* tenant.

62. In the end, we acknowledge our thanks to the learned counsels for the parties and learned *amicus curiae* for rendering their valuable assistance to this Board in deciding the above questions.
63. The records of the four D.B. appeals be sent back to the concerned Benches to decide the matters expeditiously in the light of the decisions made by us to the aforesaid questions of law.
64. A copy of this judgment be circulated amongst all the Members of this Board and all the Subordinate Revenue Courts in the State for decision of the pending suits and appeals in accordance with the answers given by us to the above questions of law.
65. The Registry is also directed to send copy of this judgment to the Chief Secretary, Govt. of Rajasthan for doing needful as per our aforesaid observations.

Pronounced.

(Modu Dan Detha)
Member

(V. Srinivas)
Chairman

(Chiranji Lal Dayma)
Member

(Mohan Lal Nehra)
Member

(Rajinder Kumar)
Member

* * * *

**IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN,
AJMER**

Appeal Decree No. 2012/2298/TA/Jhunjhunu.

1. Basantlal s/o Khinvanand, Caste Brahmin, r/o Buhana, Tehsil Buhana, District Jhunjhunu.
2. Dinesh,
3. Pawan,
ss/o Basantlal, Caste Brahmin
4. Bhanwar s/o Purshottam Naveera Mahaveer,
5. Mahesh Kumar,
6. Suresh Kumar,
7. Shankar Lal,
s/o Mahaveer, Caste Brahmin
8. Mahendra Singh s/o Jagmal, by caste Kumhar,
9. Mahendra Singh s/o Chhattu Singh, Caste Rajput,
all r/o village Buhana, Tehsil Buhana, District Jhunjhunu.

...Appellants

Versus

1. Narain,
2. Kishori @ Kishore,
3. Santosh Kumar,
s/o Hanuman,
4. Smt. Asha Kaushik W/o Kishore,
all Brahmin by caste, residents of village Buhana, Tehsil Buhana, District Jhunjhunu.
5. State of Rajasthan through Tehsildar, Buhana, District Jhunjhunu.

... Respondents

D.B.

Shri Mukesh Kumar Sharma, Chairman

Shri Rajinder Kumar, Member

Present:

Shri Atma Ram Sharma, counsel for appellants.

None on behalf of the respondents.

J U D G M E N T

Dated: 23-01-2019

Per Se Shri Rajinder Kumar, Member

1. This second appeal under Section 225 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 has been preferred by the defendants/appellants against the judgment and decree dated 12.3.2012 of the learned Revenue Appellate Authority, Sikar passed in Appeal No. 127/2011, whereby the said appeal of the plaintiffs/respondents No. 1 to 4 was accepted and suit was remanded to the trial court for passing the judgment afresh in the light of the observations contained therein.
2. Facts of the case in nut-shell are that the plaintiffs/respondents No. 1 to 4 filed the aforesaid suit in the Court of Sub Divisional Officer, Buhana regarding partition of the lands bearing khasra No. 715, 716, 117 and 720 situated in village Buhana. The suit was contested by the defendants/appellants by filing written statement thereto. In addition to it, they also filed a counter-claim to the suit seeking the relief of declaration of khatedari rights in respect of the suit lands and also for deleting the names of the plaintiffs/respondents No. 1 to 4 from the revenue record. The learned trial court framed as many as six issues and after recording evidence of the parties dismissed the suit of the plaintiffs/respondents and decreed the counter claim of the defendants/appellants. Assailing the said judgment and decree dated 19.10.2011, the plaintiffs/respondents No. 1 to 4 filed an appeal in the court of learned first appellate court, which came to be accepted as aforesaid. Hence, this second appeal by the defendants/appellants.

3. On 23.10.2018 and 8.1.2018, none appeared on behalf of the respondents. Therefore, we heard learned counsel for the appellants on 8.1.2018.
4. On behalf of the appellants, it was argued that sufficient evidence was available on record to decide appeal of the respondents/plaintiffs on merits but the learned first appellate court instead of doing so, remanded the matter to the trial court for deciding the suit afresh. None of the grounds contained in Order 41 for remand of the case were available on record. Therefore, the first appellate court committed material illegality in passing the impugned judgment. In addition to it, the plaintiffs/respondents were bound to file two separate appeals impugning the trial court's judgment and decree, as their suit was dismissed in its entirety and the counter claim of the defendants/appellants was decreed. Therefore, the single appeal filed in the court of the learned Revenue Appellate Authority was barred by the principle of res-judicata. Therefore, a prayer was made to accept this appeal and set aside the impugned judgment of the first appellate court.
5. We have given our thoughtful consideration to the above submissions and perused the record carefully.
6. The question of law involved herein is whether the plaintiffs/respondents no. 1 to 4 were bound to file two separate appeals in the court of learned Revenue Appellate Authority, Sikar against the judgment of the trial court, whereby their suit was dismissed in its entirety and the counter claim of the defendants/appellants was decreed or the single appeal filed by them was maintainable?
7. A cursory look at Order VIII Rule 6 of the Code of Civil Procedure, 1908 would reveal that a counter-claim is a cross-suit with all the trappings of a separate suit. In Premier Tyres Ltd Vs Kerala State Road Transport Corporation (AIR 1993 SC 1202), the Hon'ble Supreme Court has held as under:-

"Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal

against a judgment or decree..... Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

8. The question as to the impact of the principle of res-judicata in a case wherein the suit is resisted by a defendant not only by denying the plaintiff's claim, but by raising a counter-claim, was examined by Hon'ble Kerala High Court in *Girija & ors Vs. Rajan & ors* (R.S.A. No. 14 of 2015 decided on 28.01.2015) and after discussing a catena of decisions on the subject, it was observed as under:-

"From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged."

Thereafter, the Hon'ble High Court held as under:-

"Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. Facts of the present case are squarely covered by the ratio decidendi laid down in the above cases. Here also the plaintiffs/respondents No. 1 to 4 were bound to file two separate appeals against the judgment of the trial court, whereby their suit was dismissed and counter claim of appellants/defendants was decreed. Having failed to do so, only one appeal filed by them before the first appellate court was barred by the principle of res-judicata. In this regard, reliance is placed on a Larger Bench Judgment of the Hon'ble Supreme Court in *'Lonankutty Vs Thomman'* reported as AIR 1976

S.C. 1645. In that case, the Hon'ble Supreme Court held that the circumstance that the court has disposed of the matters by common judgment cannot effect the applicability of Section 11 of the Civil Procedure Code, 1908. Therefore, question of law framed above is accordingly answered in favour of the appellants/defendants.

10. In view of the above discussion, material illegality was committed by the learned first appellate court in accepting the appeal and remanding the case to the trial court for fresh adjudication. This appeal, therefore, deserves to be accepted.
11. Resultantly, the second appeal filed by the defendants/appellants is accepted. The impugned judgment and decreed dated 12.03.2012 of the first appellate court is set aside and the judgment and decree dated 19.10.2011 of the trial court is restored.

Pronounced.

(Rajinder Kumar)
Member

(Mukesh Kumar Sharma)
Chairman



IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Appeal Decree/TA/3800/2015/Jaipur

1. Hanuman son of Jankya (deceased) through LRs:-
1/1 Madan Bawaria son of Hanuman resident of Gadari Tehsil
Phulera, Distt. Jaipur,
1/2 Bhanwri wife of Devkaran daughter of Hanuman resident of
Ugariyawas Tehsil Dudu Distt. Jaipur,
1/3 Kamli wife of Madan daughter of Hanuman resident of
Ugariyawas Tehsil Dudu Distt. Jaipur.
2. Kanudi wife of Chauthu Bawaria resident of Gadari Tehsil
Phulera, Distt. Jaipur.

...Appellants.

Versus

1. Chief Secretary, State of Rajasthan, Jaipur,
2. District Collector Jaipur Distt. Jaipur.
3. Tehsildar, Tehsil Kishangarh Renwal Distt. Jaipur.

...Respondents.

D.B.

Shri Mukesh Kumar Sharma, Chairman

Shri Rajinder Kumar, Member

Argued by:-

Shri B.L. Verma, counsel for the appellants.

Shri R.P. Sharma, Dy. Govt. Advocate for the respondents.

J U D G M E N T

Date: 23.01.2019

Per Shri Rajinder Kumar, Member

1. This second appeal was preferred by the plaintiffs/ appellants under section 224 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 against the judgment and decree dated 14.10.2014 of the learned Revenue Appellate Authority, Jaipur whereby the first appeal filed by them against the judgment and decree dated 4.11.2009 of the trial court of Sub Divisional Officer, Jaipur was dismissed. By the said judgment, the learned trial court had dismissed the plaintiffs/ appellants' suit for the relief of declaration and decreed the same for the relief of permanent injunction.
2. Facts of the case in hand are that in their suit the plaintiffs-appellants alleged that the plaintiff Hanuman and the deceased Nathu were in cultivatory possession of the suit land since prior to the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. The possession of the plaintiff-appellant Hanuman over the suit land is continuing till date and after the death of the deceased Nathu, the plaintiff-appellant No. 2 is in possession of the same. On 22.12.1992, the Tehsildar regularized the disputed land in favour of the plaintiff-appellant Hanuman and Nathu on the basis of their old possession and also sanctioned mutation of the said lands in their favour. In the like manner, the lands of other khasra numbers were regularized in the names of the respective occupants. The plaintiffs-appellants are the members of the Scheduled Tribe and therefore, few villagers laid a challenge to the orders of the Tehsildar by which lands were regularised in favour of the plaintiffs-appellants by filing appeals in the court of Additional Collector (II) Jaipur. The said appeals were accepted by the appellate court setting aside the regularisation orders passed by the Tehsildar and the matters were remanded to the Sub-Divisional Officer with a direction to first of all obtain sanction from the State Government regarding the regularization of the said lands under section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and thereafter, to submit the matter to the Land Allotment Committee. The plaintiffs further pleaded in their suit that the concerned Sub-Divisional Officer has not so far initiated the proceedings under section 16 of

the Act. In the revenue record, the disputed lands have been wrongly entered as 'gair mumkin talai' whereas the plaintiffs-appellants are cultivating the same since prior to the commencement of the Tenancy Act, 1955. Therefore, a prayer was made to declare the plaintiffs-appellants as khatedars of the suit lands and to restrain the defendants from interfering into their possession over the same. The suit was contested by the defendants/ respondents alleging that the nature of the disputed lands is 'gair mumkin talai' and therefore, the same cannot be regularized. A prayer was made to dismiss the suit. The parties were put to trial and after recording the evidence, the learned trial court partly decreed the suit in the manner indicated above. The appeal filed by the plaintiffs-appellants was dismissed by the learned Revenue Appellate Authority, Jaipur vide the judgment and decree impugned herein. Hence, this second appeal.

3. We have heard the learned counsels.
4. On behalf of the plaintiffs-appellants, it was argued that there has been a little delay in filing this appeal which may be condoned in the facts and circumstances of the case. He further argued that the possession of the plaintiff-appellant No. 1 Hanuman and the husband of the appellant No. 2 since prior to commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 is proved by oral and documentary evidence on record. After the death of the deceased Nathu, his wife appellant No. 2 is continuing in possession of the disputed lands. He further submitted that the disputed lands were once regularised by the Tehsildar in favour of Hanuman and Nathur but the said order was illegally set aside by the Additional Collector in appeal. The directions given by the said appellate court have not been complied with by Sub-Divisional Officer till date and the defendants/ respondents also started interfering in the peaceful possession of the plaintiffs-appellants over the suit lands. That is why, they had to file the present suit. The courts below have given concurrent findings that the plaintiffs-appellants are occupying the suit lands since last more than sixty years. Therefore, their khatedari rights over the suit lands have matured and they were

entitled to get the decree of declaration also but the courts below illegally dismissed the suit/ appeal of the plaintiffs-appellants regarding that relief. Learned counsel also argued that the lands of other khasra numbers have been regularised in the names of other occupants but due to their weak position, the order of regularisation made in favour of the plaintiffs-appellants was illegally set aside by the Additional Collector in appeal. Therefore, a prayer was made to accept this appeal and decree the suit of the plaintiffs-appellants in entirety.

5. Learned Dy. Govt. Advocate vehemently opposed the above submissions. He canvassed that the delay in filing the appeal was intentional and thus the appeal is liable to be dismissed as time barred. He further submitted that the disputed lands are 'gair mumkin talai lands' and the same could not be regularized as per the provisions of section 16 of the Act. The previous order of the Tehsildar regularizing the disputed lands was nonest and thus, the same was rightly set aside in appeal. The Additional Collector merely gave a direction that the Sub Divisional Officer can seek permission of the State Government regarding the change of the nature of the land and then submit the matter before the Land Allotment Committee, if he deems fit. As the 'gair mumkin talai land' cannot be used for cultivatory purposes, therefore, the possession of the plaintiffs-appellants over the disputed lands is unauthorized and they cannot seek any declaration from the court. The decree of the trial court granting the relief of permanent injunction is also illegal. He has further argued that though the State Government did not prefer any appeal against the judgment and decree of the trial court yet this Board has ample power to modify the said judgment and dismiss the suit of the plaintiffs-appellants in toto. In support of his arguments he placed reliance on the following citations:-

- (i) 2001(8) RBJ 'Municipal Corporation Vs. Bahadur Raj Mehta' - In this case, it was held by the Hon'ble Rajasthan High Court that the appellate court can mould the relief according to facts of the case even in favour of the parties who have not filed any appeal or objection.

- (ii) 1981 RRD 255 'Banney Singh Vs. Badri' - In this case, a Larger Bench of this Board held that the provisions of Order 41 of the Civil Procedure Code are applicable in second appeals also.
 - (iii) 2013 (20) RBJ 617 'Teja Ram Vs. State' - In this case, it was held by this Board that no khatedari rights shall accrue on the land which is classified as 'gair mumkin talai' in the revenue record right from the beginning.
6. We have given our thoughtful consideration to the rival contentions and perused the record carefully.
 7. There has been a delay of only five months in filing this appeal. An application seeking delay condonation supported by the affidavit of the appellant has been filed. The said delay is neither inordinate nor intentional. Hence the delay in filing this appeal is condoned.
 8. The courts below have concurred on facts that right from the beginning the disputed lands are recorded as 'gair mumkin talai lands'. Therefore, the relief of declaration claimed by the plaintiffs-appellants was not granted to them by the courts below by placing reliance on Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.
 9. It is pertinent that the Hon'ble Rajasthan High Court in D.B. Civil Writ no. 1536/2003 'Abdul Rehman Vs. State' has passed directions for restoring the catchment areas to their original shape. Therefore, in dismissing the appeal, the learned first appellate court has also cited the judgment passed by Hon'ble Rajasthan High Court in Abdul Rehman's case (supra) and came to the conclusion that khatedari rights cannot be conferred in respect of the lands which are recorded as 'gair mumkin talai lands' in the revenue record. The concurrent findings of facts recorded by the courts below are neither perverse nor illegal.
 10. On the basis of the previous order dated 28.6.1993 passed by the Sub-Divisional Officer (II) Jaipur, the learned trial court has passed the decree of permanent injunction in favour of the plaintiffs-appellants. Though the State Government has not filed a separate appeal or written cross objections against the said judgment and

decree but in our considered opinion and in view of the law laid down by the Hon'ble Rajasthan High Court in Abdul Rehman case (supra), the trial court was not justified in granting the relief of permanent injunction in favour of the plaintiffs-appellants.

11. It is apposite here to quote Rule 4 of the Rajasthan Land Revenue [Allotment of Land For Agricultural Purposes] Rules 1970:-

"4. Land not available for allotment under these rules. - The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

- (i) Lands mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955:
- (ii) Lands demarcated as landing grounds for aircrafts:
- (iii) Lands reserved for village forests constituted under section 28 of the Rajasthan Forests Act, 1954 (Rajasthan Act 13 of 1954):
- (iv) Small Baras of lands reserved for thrashing grounds adjoining, or close to the Abadi of a village:
- [(v) Lands within-
 - (a) a radius of three miles of municipal limits of cities having a population of five lacs or more:
 - (b) a radius of two miles of municipal limits of towns with a population of two lacs or more, but below five lacs:
 - (c) a radius of one mile of municipal limits of towns with a population of one lac or more, but below two lacs:
 - (d) municipal limits of any other towns:
 - (e) one hundred yards of a railway fencing: or
 - (f) fifty yards from the centre of national highway or another mettled or gravelled road].
- (vi) Lands declared as saline areas under the Rajasthan Land Revenue (Saline Areas Allotment) Rules, 1962: or

- (vii) Lands reserved for allotment under any special Rides for the allotment of land."

As the disputed lands are covered under Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, therefore, the same are not available for allotment for agricultural purposes. If the impugned judgment and decree of the court below granting the relief of permanent injunction to the plaintiffs/appellants are allowed to maintain, the same would amount to giving a permission to the plaintiffs-appellants to cultivate the 'gair mumkin talai lands' against the legal provisions and in disregard of the judgment passed by the Hon'ble High Court in Abdul Rehman's case (supra). Therefore, apart from dismissing this appeal, we are inclined to modify the judgments and decrees of both the courts below by passing a decree of the dismissal of suit in its entirety with further direction to the Tehsildar concerned to initiate appropriate proceedings for eviction of the plaintiffs-appellants from the disputed 'gair mumkin talai lands'.

10. Resultantly, the appeal is dismissed. The judgments and decrees passed by the court below are modified and the suit filed by the plaintiffs/appellants stands dismissed. The concerned Tehsildar shall initiate appropriate legal proceedings against the plaintiffs-appellants for their eviction from the suit lands.

Pronounced.

(Rajinder Kumar)
Member

(Mukesh Kumar Sharma)
Chairman

**IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN,
AJMER**

Revision No.7383/2007/TA/Jhunjhunu:

1. Phoolchand aged 57 years s/o Ganpatdas
2. Birdichand aged 50 years s/o Ganpatdas
3. Indraj aged 48 years s/o Ganpatdas
4. Sohni Devi aged 75 years w/o Ganpatdas

All Swami by caste, rs/o Ajadi Kala, Tehsil and Distt. Jhunjhunu.

... Revisionists.

Versus

1. Amarsingh aged 40 years s/o Sh. Kanadas
2. Saraswati Devi aged 60 years wd/o Late Kanadas
3. Omprakash aged 35 years s/o Sh. Jhavardas
4. Patori Devi aged 55 years wd/o Jhavardas

All Swami by caste, rs/o Ajadi Kala, Tehsil and Distt. Jhunjhunu.

5. Gulab s/o Jhavardas, Caste Swami, r/o Ajadi Kala, Tehsil and Distt. Jhunjhunu.
6. State of Rajasthan through Tehsildar, Jhunjhunu (Raj.)

... Respondents.

S.B.

Shri Rajinder Kumar, Member

Argued by :

Shri Akhilesh Kumar Saini, Counsel for the revisionists.

None on behalf of the respondents.

* * *

J U D G M E N T

Dated : 07.01.2019

1. This Revision petition is directed against the order dated 12.06.2007 of the learned trial court of Sub-Divisional Officer,

Jhunjhunu passed in suit no. 08/2005, whereby the application under Order 14 Rule 5 CPC submitted by the defendants/revisionists was dismissed.

2. Facts of the case in nutshell are that a suit for declaration, permanent injunction and partition of the agricultural lands situate in Village Ajadi Kala and Bas Nanag was filed by the plaintiffs/respondents in the trial court. After submission of the written statement by the defendants/revisionists, the trial court framed only two issues, which are as follows:-

- i). Whether the plaintiffs are entitled to be declared as khatedars of the suit land after seeking its partition and to restrain the defendants by way of permanent injunction as per plaint averments?

- ii). Relief.

On 26.09.2006 the defendants/revisionists submitted an application under Order 14 Rule 5 CPC for framing three additional issues on the basis of the allegations contained in their written statement. The learned trial court dismissed the said application vide the impugned order dated 12.06.2007. Hence this revision.

3. On 21.12.2018 the arguments were heard. No one appeared on behalf of the plaintiffs/respondents.
4. Learned counsel for the defendants/revisionists submitted that the suit was contested by the defendants/revisionists on the grounds, inter-alia, that the suit land was the self acquired land of the deceased Ganpat Ram and after his death, it was inherited by the defendants/revisionists and mutation was accordingly sanctioned in their name. The learned trial court, however, did not frame any issue on the basis of averments contained in their written statement. Thereafter, the defendants/revisionists submitted an application for framing three additional issues in this regard but the learned trial court illegally dismissed the application by a non-speaking order. Therefore, a prayer was made to accept the revision petition and remand the matter to the trial court to pass a speaking order on the

application filed by the defendants/revisionists under Order 14 Rule 5 CPC.

5. After giving consideration to the rival submissions and upon perusal of record, it is revealed that the defendants/revisionists had contested the suit by filing written statement in which a number of additional pleas were taken by them. The learned trial court, however, did not take into consideration the submissions made by them while framing issues. Each material proposition affirmed by one party and denied by the other forms the subject of a distinct issue [Order 14 Rule 1 (3) CPC]. The learned trial court, however, failed to take into consideration the said provisions of while framing issues. An application filed by the defendants/revisionists Under Order 14 Rule 5 CPC for framing additional issues was also dismissed by the trial court without assigning any reason.
6. In Assistant Commissioner Commercial Tax Department Vs. Shukla & Brothers 2010 (4) SCC 785, the Hon'ble Supreme Court has deprecated the practice of the courts passing cryptic and non-speaking orders. The Hon'ble Supreme Court held thus:-

"Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases.... Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent.... The Court cannot lose sight of the fact that a losing litigant has a cause to plead and a right to challenge the order if it is adverse to him. Opinion of the Court alone can explain the cause which led to passing of the final order. Whether an argument was rejected validly or otherwise, reasoning of the order alone can show. To evaluate the submissions is obligation of the Court and to know the reasons for rejection of its contention is a legitimate expectation on the part of the litigant. Another facet of providing reasoning is to give it a value of precedent which can help in reduction of frivolous litigation."

In AIR 2003 SC 4664 'Raj Kishore Jha Vs State of Bihar and others', it was held by the Hon'ble Supreme Court that "Reason is the heartbeat of every conclusion and without the same, it becomes lifeless."

7. In view of the above legal propositions, it can be said that in every judicial order, reasons must be assigned. In the instant case, it was obligatory for the trial court to take note of the arguments of the defendants/revisionists on the basis of which they insisted that additional issues are required to be framed and the arguments of the plaintiffs/respondents on the basis of which they sought to establish that the said application was required to be dismissed. Thereafter, the findings ought to have been arrived at supported by reasons. The learned trial court did not do such exercise. Therefore, the order impugned passed by the trial court cannot be sustained and is liable to be interfered with. The revision petition merits acceptance.
8. Resultantly, the revision petition is accepted and the impugned order passed by the trial court is set aside with a direction to decide the application under Order 14 Rule 5 CPC filed by the defendants/revisionists afresh. It is expected that the above legal aspects shall be kept in mind by the trial court while deciding the application.

Pronounced.

(Rajinder Kumar)
Member



IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN,
AJMER

Appeal/LR/3637/2005/Hanumangarh

Balram s/o Ramchandra Jat, r/o Gram Norangdesar, Tehsil and District Hanumangarh

...Appellant.

Versus

1. Nikuram adopted s/o Smt. Paridevi Jat r/o Gram Norangdesar Tehsil and District Hanumangarh
2. The State of Rajasthan through Tehsildar (Revenue Hanumangarh)

...Respondents.

S.B.

Shri Rajinder Kumar, Member

Present :-

Shri Shashi Kant Joshi, Counsel for the Appellant.

Shri K.K.Purohit, Counsel for the Respondent.

J U D G M E N T

Dated: 02-01-2019

1. This second appeal under section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 is preferred against the judgment dated 21.6.2005 of the learned Revenue Appellate Authority, Hanumangarh passed in appeal No.19/2005.
2. Facts of the appeal in nutshell are that the appellant and the respondent no.1 filed separate applications for allotment of small patch of land situated in chak 13 NDR, Stone no.153/315 killa nos.5, 6, 24 and 25 of Tehsil Hanumangarh. The Sub Divisional Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Hanumangarh vide order dated 26.12.2009 ordered to allot the lands of Killa No.5 and 6 to the appellant and the land of Killa No.24 and 25 to the respondent No.1. The cost of the land was determined as four times the value of the land treating the same as „Johad Paytan “.Assailing the said order, an appeal no.19/05 was preferred by the appellant in the court of learned Revenue Appellate Authority, Hanumangarh which came to be accepted in

its entirety vide the judgment dated 21.6.2005. Despite it, the appellant has filed this second appeal against the judgment passed in the first appeal for the reasons best known to him.

3. I have heard learned counsels for the parties.
4. Learned counsel for the appellant submitted that though the first appeal of the appellant was accepted yet the first appellate court illegally remanded the matter to the allotment authority and hence, the appellant had to prefer this appeal.
5. Learned counsel for the respondent no.1 submitted that this appeal is nothing but an abuse of the process of this court and thus, it is required to be dismissed with heavy costs.
6. Having given my anxious consideration to the above submissions and upon perusal of the impugned judgment, it is revealed that the entire land was allotted in favour of the appellant by the first appellate court and that too at the rates proposed by him. Therefore, all the grievances of the present appellant stood satisfied by passing of the impugned judgment and still he has filed this second appeal without any factual or legal basis either to delay the payment of the cost of the land or to unnecessarily harass the respondents, which is an abuse of the process of the court. The appellant has filed this frivolous and vexatious appeal without reasonable ground with an easy approach "Let the court decide it." This Board strongly condemns this approach of the appellant.

Therefore, this appeal is liable to be dismissed with a cost of Rs. 25,000/-.

7. Resultantly, the appeal in hand is dismissed with a cost of Rs.25,000/-. The appellant shall deposit this amount with the Registry of this Board within a period of thirty days from today. Out of the said amount, a sum of Rs.5,000/- shall be paid personally to the respondent no.1 and the remaining amount shall be deposited with the District Legal Services Authority, Ajmer. If the appellant fails to deposit this amount within the stipulated period, the same shall be recovered from him in accordance with law by initiating separate recovery proceedings against him under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Pronounced.

(Rajinder Kumar)
Member

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/515/2005/जैसलमेर

राणे खां पुत्र रायधन खां जाति मुसलमान निवासी देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, जैसलमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री मोड़दान देथा, सदस्य

उपस्थित: श्री अशोक अग्रवाल वकील एवं
श्री डूंगरसिंह राठौड़ वकील अपीलार्थी।
श्री वी.पी.सिंह राजावत राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक: 2.1.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 2/04 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.9.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम अमरपुरा (देवीकोट) में वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि स्थित है। समरी बन्दोबस्त में इसके खसरा नम्बर 111 रकबा 23 बीघा ही दर्ज किये गये जबकि वादी का कब्जा 57 बीघा 10 बिस्वा पर चला आ रहा है। स्थाई बन्दोबस्त में इसके खसरा नम्बर 1074 रकबा 24.12 बीघा ग्राम देवीकोट वादी के नाम

दर्ज किये गये। दौराने पैमाईश उक्त खसरा नम्बर 1074 देवीकोट ग्राम में थी परन्तु बाद में इसे अमरपुरा गांव घोषित किया गया एवं 1074 के नये खसरा नम्बर 380 कायम किये गये। खसरा नम्बर 380 से लगते उत्तर की ओर खसरा नम्बर 388 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा को वादी की शेष भूमि शामिल कर भू प्रबन्ध के दौरान सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काशत पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अतः खसरा नम्बर 388 में 32 बीघा 8 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ़ ने निर्णय दिनांक 28.4.2004 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाडमेर-जैसलमेर) मुं० जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.9.2004 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि समरी बन्दोबस्त से पूर्व जैसलमेर का कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ था। समरी बन्दोबस्त में भूमि अंदाजिया दर्ज की जाती थी जिससे खसरा नम्बर 111 का रकबा 23 बीघा ही दर्ज हो पाया जबकि वादी अपीलार्थी का कब्जा काशत 57.10 बीघा पर पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। स्थाई बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 111 के खसरा नम्बर 1074 कायम किये जाकर रकबा 24.12 बीघा ही वादी के नाम दर्ज किया गया। शेष रकबा 1082 में दर्ज कर दिया गया। अमरपुरा गांव बनने पर खसरा नम्बर 1074 के खसरा नम्बर 380 कायम किये गये तथा खसरा नम्बर 1082 से खसरा नम्बर 388 कायम किये गये। खसरा नम्बर 380 से लगती हुई खसरा नम्बर 388 की 32 बीघा 8 बिस्वा पर वादी अपीलार्थी का कब्जा काशत चला आ रहा है परन्तु बन्दोबस्त के दौरान इसे सिवायचक दर्ज कर दिया जो अनुचित एवं निराधार है। विचारण न्यायालय ने सभी तनकियात पर साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। वादी अपीलार्थी के सभी गवाहों ने वादी का कब्जा काशत पूर्वजों के समय से होना बताया है फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर साक्ष्यों पर विश्वास नहीं करने में भूल की है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही सिवायचक रही है तथा बन्दोबस्त में सही रूप से सिवायचक दर्ज की गई है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 388 पर वादी अपीलार्थी का सम्वत 2012 एवं उससे पूर्व से कब्जा काशत होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। केवल मौखिक

साक्ष्य के आधार पर वादी डिक्री नहीं किया जा सकता। वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से वादी अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काशत सम्वत 2058 में अतिक्रमी के रूप में होना पाया जाता है। एक दो वर्ष के अतिक्रमी को राजकीय सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। समरी बन्दोबस्त में वादी अपीलार्थी के नाम खसरा नम्बर 111 की 23 बीघा पर कब्जा होने से उसके नाम दर्ज की गई है। समरी बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 111 के नवीन खसरा नम्बर 1074 रकबा 24.12 बीघा बने जो वादी अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं। राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादी अपीलार्थी जितनी भूमि पर काबिज था वह उसके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। हाल खसरा नम्बर 388 पर वादी का राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय कब्जा काशत होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. जहां तक समरी की किसी त्रुटि के कथन का प्रश्न है, प्रथम तो कोई त्रुटि नहीं थी, द्वितीय इनके स्वयं के कथनों अनुसार समरी में रकबा 23 बीघा इनके नाम था जो भू प्रबन्ध में 24.12 बीघा हो गया। यह प्रकट करता है कि यदि कोई गलती तर्क के लिए थी भी तो भू प्रबन्ध में नाप-जोख कर दुरुस्त करदी गई। इनका वादपत्र में यह कथन है कि 24 बीघा 12 बिस्वा का पर्चा लगान प्रदान किया। यह इनका अभिवचन है और अभिवचन एक उत्तम साक्ष्य है जब पर्चा लगान दिया गया तो लगान का गणन का आधार रकबा होता है और पर्चा देने पर इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की। जब पर्चा प्रदान करने का कथन है और इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की तो लगान की अदायगी की स्वीकारोक्ति मानी जाएगी और लगान क्षेत्रफल अनुसार रहता है। जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से अपील स्वीकार की है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

6. जबाब बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि समरी से पूर्व का अभिलेख जैसलमेर रियासत क्षेत्र में नहीं था। प्रथम बार बना रेकर्ड त्रुटिपूर्ण होने से हमने इसे चुनौति दी है जो पश्चात के वर्षों में हमारा कब्जा काशत रेकर्ड से प्रकट होता है। जहां पूर्व रेकर्ड बना ही नहीं है, वहां मौखिक साक्ष्य अधिकार के निर्धारण का एकमेव आधार रहेगा। ऐसा कई निर्णयज विधि में प्रतिपादित है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2058, जुर्माना रसीद सम्वत 2052 व मौखिक साक्ष्यों को आधार बनाकर तनकी संख्या 1, 2, 3 का निर्णय वादी अपीलार्थी के पक्ष में करते हुए वादी का

स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि सम्वत 2012 से विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काशत होना प्रमाणित नहीं होता है तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता, विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया है।

9. इस वाद में वादी अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा है कि हाल खसरा नम्बर 388 के रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा पर वादी अपीलार्थी का कब्जा काशत पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। समरी बन्दोबस्त में कब्जे के विपरीत मात्र 23 बीघा ही वादी के नाम दर्ज की गई है जबकि 57.10 बीघा दर्ज की जानी चाहिये थी। वाद को साबित कराने का दायित्व वादी का स्वयं का होता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद को साबित कराने हेतु यह आवश्यक है कि वादी अपीलार्थी राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय विवादित भूमि पर स्वयं का काशतयुक्त विधिपूर्ण कब्जा होना साबित करें। इस संबंध में वादी अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 388 पर वादी का राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय कब्जा काशत होना प्रमाणित होता हो। वादी अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में मात्र सम्वत 2052 की एक 4 रुपये की जुर्माना रसीद तथा सम्वत 2058 का खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत किया है। खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि सम्वत 2058 में वादी अपीलार्थी ने 6 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर काशत की है। जबकि वादी का कथन है कि उसका कब्जा 32.8 बीघा पर चला आ रहा है। जो किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

10. समरी बन्दोबस्त के समय वादी का कब्जा काशत 23 बीघा रकबे पर होने से खसरा नम्बर 111 रकबा 23 बीघा वादी अपीलार्थी के नाम दर्ज किये गये जिसके नवीन खसरा नम्बर 1074 रकबा 24.12 बीघा बने जो स्थाई बन्दोबस्त में वादी के नाम दर्ज किये गये हैं। हाल खसरा नम्बर 388 वादी के कब्जे काशत में होकर समरी में दर्ज रहा था अथवा समरी पूर्व विधिपूर्ण आधिपत्य में था सप्रमाण साक्ष्य से पुष्ट नहीं है। जब वादी का वाद कथन (अभिवचन) यह है कि भू प्रबन्ध ने पर्चा प्रदान किया था तो उस समय आपत्ति क्यों नहीं की। पर्चा लगान की अस्वीकारोक्ति (इंकार) का अभाव यह प्रकट करता है कि लगान स्वीकार किया गया और लगान की गणना का आधार क्षेत्रफल रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि तत्समय वादी ने अपना अधिकार नहीं होने से चाराजोही नहीं की तथा इस देरी की स्थिति को वादी ने स्वतः स्पष्ट युक्तियुक्त आधार से स्पष्ट नहीं किया है। समरी के ठीक पश्चात एवं भू प्रबन्ध के ठीक पश्चात जब अभिलेख का वर्तमान स्वरूप उस क्षेत्र में प्रवर्तन/प्रचलन में आ गया था, उस समय का भी वादी ने अपने कब्जे काशत का अभिलेखीय साक्ष्य से समर्थित कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख के वर्तमान

स्वरूप के उस क्षेत्र में प्रचलन में आने के काफी बाद के अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना विधि की मंशा नहीं है। ऐसी स्थिति दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। प्रथम अपील न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर-जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.9.2004 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहूदान देथा)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष



न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील/एलआर/5323/2010/राजसमन्द

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द
अपीलार्थी

बनाम

1. भैरू पुत्र नाथू
2. मुं0 घीसी पुत्री मोती जाति बलाई निवासीयान रेलमगरा तहसील
रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री मोड़दान देथा, सदस्य

उपस्थित: श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरुका उप राजकीय अभिभाषक।

श्री मुकेश जैन वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक:..2.1.19

यह स्पेशल अपील धारा 10 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा निग/एलआर/32/01 जिला राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 11.11.05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा मौजा रेलमगरा की आराजी खसरा नम्बर 997 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर अतिक्रमण कर लिये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार, रेलमगरा ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 18.5.98 से बेदखली, कायमी पेनाल्टी एवं धारा 91(6) अधिनियम के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध वर्तमान अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 27.7.98 से खारिज की गई। इसके

विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 29.3.2001 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या एलआर/32/ 01/ राजसमन्द प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 11.11.05 से आंशिक रूप से स्वीकार की गई। इससे असन्तुष्ट होकर राज्य पक्ष की ओर से यह स्पेशल अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। स्पेशल अपील संख्या 7206/06 निर्णय दिनांक 12.3.10 से स्वीकार की गई। इसके विरुद्ध वर्तमान अप्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 2746/10 प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 25.8.10 से स्वीकार किया जाकर स्पेशल अपील में खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.3.2010 निरस्त किया गया एवं स्पेशल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया गया। जिससे यह स्पेशल अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी राजकीय बिलानाम भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित की हुई गैर मु० भूमि है। ऐसी भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता। राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ ने साक्ष्यों एवं तथ्यों को देखे बिना ही तीन माह में आवेदन करने एवं बाड़ा नियमन करने का आदेश दिया है जो विधि विरुद्ध है। बाड़ा आवंटन अथवा नियमन हेतु अलग से नियम बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत अलग से कार्यवाही करनी होगी। वर्तमान प्रकरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से बेदखली का है जिसमें बाड़ा नियमन नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का 1980 से कब्जा होना भी साबित नहीं है। प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनका वर्ष 1980 से बाड़ा बना हुआ होकर कब्जा होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में एकल पीठ का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होने से यह स्पेशल अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर वर्ष 1980 के पूर्व से प्रत्यर्थीगण बाड़ा बनाकर काबिज चले आ रहे हैं। बाड़े में अपने पशु बांधते हैं एवं कृषि के उपयोग में लेते हैं। प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर दिये जाने से काफी नुकसान व परेशानी होगी। प्रत्यर्थीगण का कब्जा नियमन योग्य है तथा विवादित भूमि बिलानाम सरकार है। किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं है। प्रत्यर्थीगण का प्रकरण नियमन योग्य है। धारा 91 अधिनियम की कार्यवाही में भी नियमन का आदेश दिया जा सकता है। जिससे एकल पीठ का निर्णय विधि अनुरूप होने से यह स्पेशल अपील खारिज की जावे।

5.. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित बिलानाम भूमि है। प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार, रेलमगरा ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 18.5.98 से बेदखली, कायमी पेनाल्टी एवं धारा 91(6) के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय दिनांक 27.7.98 से तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को प्रस्तुत द्वितीय अपील निर्णय दिनांक 29.3.2001 से खारिज की गई। इसके विरुद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी को एकल पीठ ने निर्णय दिनांक 11.11.05 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी वर्तमान प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार बाड़ा प्राप्त करने हेतु आवेदन व नियत राशि तीन माह में जमा कराने का आदेश दिया। जिस पर संबंधित तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करें, निर्देश दिये।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। प्रत्यर्थीगण अतिक्रमी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना साबित है। प्रत्यर्थीगण का यह तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका 1980 से कब्जा है, जिससे बाड़ा नियमन किया जावे। प्रथम तो प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, द्वितीय बाड़ा आवंटन हेतु अलग से प्रावधान/निर्देश हैं जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8. वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील का नहीं होकर अतिक्रमण बेदखली का होने से इसमें विचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत विषय अतिक्रमी की बेदखली है। विचार हेतु प्रस्तुत विषय अतिक्रमण का नियमन करना नहीं होने से उस पर विचार कर निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं था। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधानित है। इस बेदखली की कार्यवाही में बाड़ा नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। साथ ही आवंटन एवं नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है। व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित होने पर आवेदन कर सकता है किन्तु स्वयं चयन कर अधिकार स्वरूप किसी भूखण्ड विशेष के आवंटन या नियमन का कथन अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। विवादित आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से भी आवंटित नहीं की जा सकती।

9. विवादित राजकीय बिलानाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह स्पेशल अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पेशल अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा निगरानी/एलआर/ 32/01/राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 11.11.05 निरस्त किया जाता है। तदनुसार निगरानी संख्या 32/01 निरस्त की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 29.3.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष



राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की वार्षिक समीक्षा

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.04.2018 से 30.06.2018 (त्रैमासिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.04.2018 से 30.06.2018 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति (ग्रेडिंग) को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्ड :- न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार पर :-

1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- 1000 या अधिक लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से 999 लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से कम लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

2- भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :-

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| (क) | 1000 या अधिक लम्बित | - 50 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 30 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |
| (ख) | 500 से 1000 लम्बित | - 30 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 15 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |
| (ग) | 500 से कम लम्बित | - 20 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 10 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है।)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन :-

(अ) मानदण्ड का 100 प्रतिशत से अधिक-उत्कृष्ट-‘ए’

1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर।

2- भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन -कोटा, सीकर।

राजस्व अपील प्राधिकारी :-

(ब) मानदण्ड का 90 % से 100 % तक - बहुत अच्छा - 'बी'

- 1 - राजस्व अपील प्राधिकारी :- -शून्य।
 2 - भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - उदयपुर।
 राजस्व अपील प्राधिकारी

(स) मानदण्ड का 80 % से 90 % तक - 'अच्छा' - 'सी'

- 1 - राजस्व अपील प्राधिकारी :- -कोटा।
 2 - भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - टोंक।
 राजस्व अपील प्राधिकारी

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक - 'औसत' - 'डी'

- 1 - राजस्व अपील प्राधिकारी :- -शून्य।
 2 - भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - शून्य।
 राजस्व अपील प्राधिकारी

(य) मानदण्ड का 70 % से नीचे - 'औसत से नीचे' - 'ई'

- 1 - राजस्व अपील प्राधिकारी :- -अलवर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर।
 2 - भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन -अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर।
 राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर व बाड़मेर एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का पद रिक्त होने के कारण समीक्षा नहीं की गई है, साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर से त्रैमासिक सूचना प्राप्त न होने के कारण समीक्षा जारी नहीं की गई है।

ग्रेड 'डी' व 'ई' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

ह./-

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(क्रमांक : राम/निरी./प.9(165)आर.ए.ए./एस.ओ./2018/6189-209 दिनांक 28.8.2018)

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-04-2018 से 30-06-2018 में निस्तारित किये गये राजस्व-प्रकरणों पर मण्डल की वार्षिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-04-2018 से 30-06-2018 में किये गये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प.12(18) राम/निरी/78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है-

निर्धारित मापदण्ड :- 10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह

त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण=60 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधार :

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	B

सम्भाग-भरतपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A+
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	A+
3	जिला कलेक्टर, करौली	A+
4	जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	A+

सम्भाग-बीकानेर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
2	जिला कलेक्टर, चूरू	A+
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	A+
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	A+

सम्भाग-जयपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	A+
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	A+

सम्भाग-जोधपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	A+
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	जिला कलेक्टर, जालौर	A+
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	A+
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	A+

सम्भाग-कोटा

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	A+
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
4	जिला कलेक्टर, कोटा	A

सम्भाग-उदयपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला-कलेक्टर, बांसवाड़ा	A+

राविरा अंक 118

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
2	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	A+
3	जिला कलेक्टर, झुंझारपुर	C
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	A+
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A+

ह.

(सूरजभान जैन)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(क्रमांक :- राम/निरी/प.9(174)/त्रैमा./जि.कले./2018/8083-8115 दिनांक 04.12.18)

पत्रिका विवरण

1. नाम - राविरा त्रैमासिक अंक - 118
2. आकार - राविरा 6.2 x 9.2 इंच
3. मुद्रित प्रतियाँ - 24,000
4. प्रयुक्त कागज - (क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम.
(ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम.
(ग) साधारण कागज (मेपलिथो)
80 से 90 जी.एस.एम.
5. प्रकाशक - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक - राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज - 4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ - 12 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ - 96 पृष्ठ

राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टरों द्वारा त्रैमासिक अवधि 01.04.2018 से 30.06.2018 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.04.2018 से 30.06.2018 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टरों द्वारा राजस्व अभियोगों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की गयी।

निर्धारित मापदण्ड :- 1-उपखण्ड अधिकारी - 15 वाद एवं 15 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

2- सहायक कलेक्टर - 20 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक - "उत्कृष्ट-ए+"

1-उपखण्ड अधिकारी :- अजमेर, ब्यावर, केकडी, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, पीसांगन, सरवाड़, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, अलवर, रामगढ़, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मागढ़, कटूमर, कि. बास, मुण्डावर, तिजारा, कोटाकासिम, बहरोड, बानसूर, निम्बराना, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, बागीडोरा, गढी आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, बारां, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, मांगरोल, शाहाबाद, छीपाबडोद, अन्ता, बाडमेर, बालोतरा, गुढामालानी, शिव, बायतू, चौहटन, रामसर, सिवाना, सणधरी, धुरीमन्ना, भरतपुर, डीग, कामां, बयाना, कुम्हेर, बैर, नदबई, रूपवास, नगर, पहाडी, भूसावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, बनेडा, माण्डल, माण्डलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर, रायपुर, बिजौलिया, कोटडी, आसींद, फूल्याकला, हमीरगढ़, करेडा, बदनोर, खाजूवाला, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर, कोलायत, बून्दी, नैनवां, के. पाटन, हिण्डौली, लाखेरी, तालेडा, चित्तौडगढ़, कपासन, निम्बाहेडा, बैगूं, बडीसादडी, गंगरार, रावतभाटा, राशमी, भदेसर, डूंगला, भूपालसागर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर, बिदासर, दौसा, बांदीकुई, महुवा, सिकराय, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़, पचवारा, धौलपुर, बाडी, बसेडी, सैपऊ, राजाखेडा, सरमथुरा, डूंगरपुर, सांगवाडा, सीमलवाडा, आसपुर, बिछीवाडा, गंगानगर, करनपुर, रायसिंहपुर, अनूपगढ़, घडसाना, सूरतगढ़, सादूलशहर, पदमपुर, विजयनगर, हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा, भादरा, जयपुर, बस्सी, जयपुर (द्वितीय), चाकसू, आमेर, कोटपूतली, सांभर, ज. रामगढ़, विराटनगर, चौमूं, शाहपुरा, दूदू, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, जालौर, आहोर, रानीवाडा, सायला, बागौडा, जसवन्तपुरा, चितलवाना, झालावाड़, भवानीमण्डी, अकलेरा, खानपुर, पिडावा, मनोहरथाना, गंगधार, झुझुनूं, चिडावा, खेतडी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, बुहाना, मल्सीसर, सुरजगढ़, जोधपुर, फलौदी, पीपाडशहर, औसियां, शेरगढ़, लूणी, भोपालगढ़, बावडी, बाप, बलेसरा, बिलाडा, करौली, हिंडौन, सपोटरा, टोडाभीम, नांदौती, कोटा, रामगंजमंडी, दीगोद, सागोद, ईटावा, कनवास, नागौर, मेडता, डीडवाना, परबतसर, जायल, डेगाना, नावां, मकराना, लाडनूं, खींवरसर, कुचामन सिटी, रियाँबडी, पाली, बाली, सोजत, जैतारण, देसूरी, सुमेरुपर, रोहट, मा. जंक्शन, रायपुर, रानी, राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, रेलमगरा, आमेर, देवगढ़, स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, बोली, बामनवास, खण्डार, चौथ का बरवाडा, मलारना डूंगर, सीकर, फतेहपुर, नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, धोद, रामगढ़, शेखावाटी, खण्डेला, सिरौही, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, टोंक, निवाई, उनियारा, देवली, पीपलू, मालपुरा, टोडारायिसंह, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली, खैरवाडा, झाडोल, कोटडा, सलूमबर, लसाडिया, ऋषभदेव, गोगुदा, प्रतापगढ़, धरियावादा।

2-सहायक कलेक्टर :- अजमेर, अलवर, बानसूर, भरतपुर, कुम्हेर, नदबई, उच्चेन, बीकानेर, दौसा,

जयपुर, जयपुर (शहर), आमेर, बस्सी, फागी, सांभर, चौमूं, कोटपूतली, कोटा, दीगोद, करौली, नागौर (मु.), गंगापुर सिटी, सीकर, सीकर द्वितीय।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक – “बहुत अच्छा-ए”

1-उपखण्ड अधिकारी :-

2-सहायक कलेक्टर :- बहरोड़

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक – “अच्छा-बी+”

1-उपखण्ड अधिकारी :-

2-सहायक कलेक्टर :-

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक – ‘औसत-बी’

1-उपखण्ड अधिकारी :- पूंगल, भीनमाल।

2-सहायक कलेक्टर :- धौलपुर, टोंक।

(ड) मानदण्ड का 70% से नीचे – ‘औसत से नीचे सी’:-

1-उपखण्ड अधिकारी :- टाडगढ़, छोटी सरवन, बीकानेर, छत्तगरढ़, सांचौर, सराडा, अरनोद, छोटीसादडी, पीपलखुंट।

2-सहायक कलेक्टर :- लालसोट, स. माधोपुर।

उपखण्ड अधिकारी रेणी, सडवा, सांवाला, गलियाकोट, चिकली, भनियाणा, बसनावर, वजीरपुर, बडगांव का पद नवसृजित/रिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

सहायक कलेक्टर बिलाडा व खंडेला के पद क्रमोन्नत होकर उपखण्ड अधिकारी हो गये हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :-

(अ) वादों का निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निस्तारण हेतु कठोर कदम उठाये जाए। प्रत्येक अधिकारी की निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वादों के निस्तारण हेतु जिम्मेदारी आरोपित की जाए एवं मानदण्ड से कम निस्तारण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(ब) जिन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार राजस्व वादों का निस्तारण नहीं किया जाता है, उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि की सिफारिश के साथ दावों के निस्तारण की स्थिति का मानचित्र वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ भेजा जाए।

(स) पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

ह./-

(श्री सूरजभान जैमन)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.07.2018 से 30.09.2018 (त्रैमासिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.07.2018 से 30.09.2018 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति (ग्रेडिंग) को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्ड :- न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार पर :-

1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- 1000 या अधिक लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से 999 लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से कम लम्बित

राजस्व मुकदमों पर - 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

2- भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी :-

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| (क) | 1000 या अधिक लम्बित | - 50 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 30 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |
| (ख) | 500 से 1000 लम्बित | - 30 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 15 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |
| (ग) | 500 से कम लम्बित | - 20 मामले बहुपक्षीय |
| | राजस्व मुकदमों पर | - 10 मामले एक पक्षीय प्रतिमाह |

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है।)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन :-

(अ) मानदण्ड का 100 प्रतिशत से अधिक-उत्कृष्ट- 'ए'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर।

2- भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन -सीकर, उदयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी :-

(ब) मानदण्ड का 90 % से 100 % तक -बहुत अच्छा- 'बी'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -शून्य।

- 2- भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - शून्य।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(स) मानदण्ड का 80 % से 90 % तक- 'अच्छा' - 'सी'

- 1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -अजमेर, अलवर, कोटा।
2- भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - शून्य।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक- 'औसत' - 'डी'

- 1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -पाली।
2- भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन - टोंक।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(य) मानदण्ड का 70 % से नीचे - 'औसत से नीचे' - 'ई'

- 1- राजस्व अपील प्राधिकारी :- -भरतपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, जोधपुर,
सवाई माधोपुर।
2- भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन -अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा।
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर व बाड़मेर का पद रिक्त होने के कारण समीक्षा नहीं की गई है।

ग्रेड 'डी' व 'ई' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

ह./-

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(क्रमांक : राम/निरी./प.9(180)आर.ए.ए./एस.ओ./2018/41-60 दिनांक 26.06.2018)

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-07-2018 से 30-09-2018 में निस्तारित किये गये राजस्व-प्रकरणों पर मण्डल की वार्षिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-07-2018 से 30-09-2018 में किये गये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प. 12(18) राम/निरी/78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है-

निर्धारित मापदण्ड :- 10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह

त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण=60 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधार :

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	C

सम्भाग-भरतपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A+
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	B
3	जिला कलेक्टर, करौली	B
4	जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	A+

सम्भाग-बीकानेर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
2	जिला कलेक्टर, चूरू	C
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	B
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	A

सम्भाग-जयपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	A+
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	B+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	A+

सम्भाग-जोधपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C+
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	जिला कलेक्टर, जालौर	C+
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	B
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	C

सम्भाग-कोटा

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बारां	A+
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	A+
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
4	जिला कलेक्टर, कोटा	A

सम्भाग-उदयपुर

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला-कलेक्टर, बांसवाड़ा	B+

राविरा अंक 118

क्रम संख्या	नाम जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
2	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	B+
3	जिला कलेक्टर, झुंजरपुर	C
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	B
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A

ह.

(सूरजभान जैन)

सदस्य

राजस्य मण्डल राजस्थान, अजमेर

(क्रमांक :- राम/निरी/प.9(178)/त्रैमा./जि.कले./2018/8796-8828 दिनांक 27.12.18)



अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01-07-2018 से 30-09-2018 में निस्तारित किये गये राजस्व-प्रकरणों पर मण्डल की वार्षिक समीक्षा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि दिनांक 01-07-2018 से 30-09-2018 में किये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है।
मण्डल के परिपत्र क्रमांक : राम/निरी/आरसीएमएस/बैठक/2015/7545-630 दिनांक 17.09.2018 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है :-

निर्धारित मानदण्ड :- प्रतिमाह 50 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि
वार्षिक / 150 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

ग्रेडिंग का आधार

1	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर

क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर	C+
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक	C

सम्भाग-भरतपुर

क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	C
6	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी (स.मा.)	C

सम्भाग-बीकानेर

क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चूरु	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगानगर (प्रथम)	B
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगानगर (सतर्कता)	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ (गंगानगर)	C
6	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C
7	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नोहर	C

सम्भाग-जयपुर

क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	C
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा	B
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
6	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	C
7	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	C
8	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
9	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	C
10	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर	C

सम्भाग-जोधपुर

क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालौर	C
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
6	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C

7	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली	C
8	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही	C
सम्भाग-कोटा		
क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां	C
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बून्दी	C
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड़	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा	C
सम्भाग-उदयपुर		
क्रम संख्या	नाम अतिरिक्त जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अतिरिक्त जिला-कलेक्टर, बांसवाड़ा	C
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	C
3	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर	C

ह.

(सदस्य)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(क्रमांक :-राम/प. 9(173)अति.जि.कले./2018/8727-8773 दिनांक : 27/12/2018)



राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टरों द्वारा त्रैमासिक अवधि 01.07.2018 से 30.09.2018 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.07.2017 से 30.09.2018 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टरों द्वारा राजस्व अभियोगों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की गयी।

निर्धारित मापदण्ड :- 1-उपखण्ड अधिकारी - 15 वाद एवं 15 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

2- सहायक कलेक्टर - 20 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक - "उत्कृष्ट-ए+"

1-उपखण्ड अधिकारी :- किशनगढ़, मुण्डावर, निम्बराना, बारां, मांगरोल, कुम्हेर, पहाडी, डूंगरपुर, गंगानगर, सूतसगढ़, सार्दुलशहर, हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा, झुझुनूं, कोटा, मेडता, देवगढ़, मालपुरा, वल्लभनगर, मावली।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक - "बहुत अच्छा-ए"

1-उपखण्ड अधिकारी :-रूपवास, पदमपुर, टिब्बी, जयपुर (द्वितीय), चाकसू, रियाबड़ी, सवाई माधोपुर।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक - "अच्छा-बी+"

1-उपखण्ड अधिकारी :- किशनगढ़, भरतपुर, बयाना, रावतसर, फलोदी, लाडनूं।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(द) मानदण्ड का 70 % से 80 % तक - 'औसत-बी'

1-उपखण्ड अधिकारी :- सरवाड, बहरोड, कामां, नगर, कोलायत, डूंगला, बांदीकुई, संगरिया, भादरा, खानपुरा, चिडावा, उदयपुरवचाटी, जैतारण, सुमेरपुर, श्रीमाधोपुर।

2-सहायक कलेक्टर :- शून्य।

(ड) मानदण्ड का 70% से नीचे - 'औसत से नीचे सी' :-

1-उपखण्ड अधिकारी :- अजमेर, ब्यावर, केकडी, नसीराबाद, मसूदा, पीसांगन, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, टाटगढ़, अलवर, रामगढ़, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कटूमर, तिजारा, कोटाकासिम, बानसूर, बांसवाडा, घाटोल, कुशलगढ़, बागीडोरा, गढी, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, छबड़ा, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, छीपाबडोद, अन्ता, बाडमेर, बालोतरा, गुढामालानी, शिव, बायतू, चौहटन, रामसर, सिवाना, सणधरी, धुरीमन्ना, डीग, बैर, नदबई, भूसावर, भीलवाडा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, बनेड़ा, माण्डल, माण्डलगढ़, गंगुपर, जहाजपुर, राजयपुर, बिजौलिया, कोटडी, आसींद, फूल्याकला, हमीरगढ़, करेडा, बदनोर, बीकानेर, खाजूवाला, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर, पूंगल, छत्तरगढ़, बून्दी, नैनवां, के. पाटन, हिण्डौली, लाखेरी, तालेड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासन, निम्बाहेड़ा, बैंगूर, बड़ीसादडी, गंगारार, रावतभाटा, राशमी, भदेसर, भूपालसागर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर, बिदासर, दौसा, महुवा, सिकराय, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़, पचवारा, धौलपुर, बाडी, बसेडी, सैंपऊ, राजाखेडा, सरमथुरा, सांगवाडा, सीमलवाडा, आसपुर, बिछीवाडा, करनपुर, रायसिंहपुर, अनूपगढ़, घडसाना, जयपुर, बस्सी, आमेर, कोटपूतली, सांभर, ज. रामगढ़,

विराटनगर, चौमूं, शाहपुरा, दूदू, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, भनियाना, जालौर, आहौर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, सायला, बागोडा, जसवनतपुरा, चितलवाना, झालावाड, भवानीमण्डी, अकलेरा, पिडावा, मनोहरधाना, गंगधार, खेतडी, नवलगढ़, बुहाना, मल्सीसर, सूरजगढ़, जोधपुर, पीपाडशहर, औसियां, शेखगढ़, लूणी, भोपालगढ़, बावडी, बाप, बलेसरा, बिलाडा, करौली, हिंडौन, मण्डरायल, सपोटरा, टोडाभीम, नादौती, रामगंजमंडी, दीगोद, सांगोद, ईटावा, कनवास, नागौर, डीडवाना, परबतसर, जायल, डेगाना, नावां, मकराना, खींवसर, कुचामन सिटी, पाली, बाली, सोजत, देसूरी, रोहट मा. जंक्शन, रायपुर, रानी, राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, रेलमगरा, आमेट, गंगापुरसिटी, बोली, बामनवास, खण्डार, चौथ का बरवडा, मलारना डूंगर, सीकर, फतेहपुर, नीमकाधाना, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, धोद, रामगढ़ शेखावाटी, खण्डेला, सिराही, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, टोंक, निवाई, उनियारा, देवली, पीपलू, टोडारायसिंह, गिर्वा, खैरवाड़ा, झाडोल, कोटडा, सलूमबर, लसाडिया, सराडा, ऋषभदेव, गोगुदा, प्रतापगढ़, धरियावाद अरनोद, छोटीसादडी, पीपलखुंट।

2-सहायक कलेक्टर :- अजमेर, अलवर, बानसूर, बहरोड, भरतपुर, कुम्हेर, नदबई, उच्चैन, बीकानेर, दौसा, लालसोट, धौलपुर, जयपुर, जयपुर (द्वितीय), आमेर, बस्सी, फागी, सांभर, चौमूं, कोटपूतली, कोटा, दीगोद, करौली, नागौर (मु.), स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, सीकर (द्वितीय), टोंक।

उपखण्ड अधिकारी रेणी, सडवा, सांवला, गलियाकोट, चिकली, भनियाना, बसनावर, वजीरपुर, बडगांव का पद नवसृजित/रिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

सहायक कलेक्टर बिलाडा व खंडेला के पद क्रमोन्नत होकर उपखण्ड अधिकारी हो गये हैं।

जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :-

(अ) वादों का निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निस्तारण हेतु कठोर कदम उठाये जाएं। प्रत्येक अधिकारी की निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वादों के निस्तारण हेतु जिम्मेदारी आरोपित की जाए एवं मानदण्ड से कम निस्तारण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

(ब) जिन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार राजस्व वादों का निस्तारण नहीं किया जाता है, उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि की सिफारिश के साथ दावों के निस्तारण की स्थिति का मानचित्र वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ भेजा जाए।

(स) पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

ह./-

(श्री सूरजभान जैमन)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि

क्रमांक: प. 9(11)राज-1/2019

जयपुर, दिनांक 30-01-2019

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जिला भीलवाड़ा की तहसील, फुलियाकलां** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जनसंख्या	क्षेत्रफल		जनसंख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भीलवाड़ा/ फुलियाकलां	धनोप	4014	2295.14	नन्दा का खेड़ा	339	127.84	2.5	2167.30

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये **जिला कलक्टर, भीलवाड़ा** को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

ह.

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जिला बून्दी की तहसील, नैनवां** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जनसंख्या	क्षेत्रफल		जनसंख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बून्दी/ नैनवां	खुरी	778	599.33	नोहरा	331	187.53	3.0	411.80

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये **जिला कलक्टर, बून्दी** को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

ह.

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जिला सीकर की तहसील, नीमकाथाना** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रक्का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जनसंख्या	क्षेत्रफल		जनसंख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीकर/ नीमकाथाना	सिरोही	12608	2242.58	चरणसिंहनगर	850	317.01	3.0	832.63
					खुडालिया	600	378.91	2.0	
					तेतरवाल्लो का बास	1250	714.03	2.0	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये **जिला कलक्टर, सीकर** को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

ह.

(शक्ति सिंह राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT**

No. F. 1(58) Rev./6/2017/02

Jaipur, Dated : 02-01-18

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi-A) of sub-section (2) of section 261 read with section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) (Amendment) Rules, 2018.

(2) The shall come into force at once.

2. Amendment of FORM-G.- In clause 4 of FORM-G appended to the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, the existing expression "residential colony/project/industrial area/industrial estate/" shall be deleted.

By order of the Governor,

(Ramniwas Jat)

Joint Secretary to the Government

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT**

No. F. 1(58) Rev./6/2017/01

Jaipur, Dated : 02-01-18

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 100 of the Rajasthan land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Industrial Areas Allotment (Amendment) Rules, 2018.

(2) The shall come into force at once.

2. Substitution of rule 7.- The existing rule 7 of the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959 shall be substituted by the following, namely :-

"7. Setting up of industry.- (1) Industry shall be set up within a period of two years from the date of allotment of land.

Provided that the allotting authority may, on the application of allottee, extend the period of setting up of industry upto two years. If allottee fails to use of land within such extended period, the allotting authority may on application of allottee refer the matter to the State Government for extension of above period. The State Government may extend the above period in appropriate cases.

(2) If the land is not used within the stipulated period or time extended as per provisions of sub-rule (1), the land shall revert back to the State Government free from all encumbrances."

By order of the Governor,

(Ramniwas Jat)

Joint Secretary to the Government

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT**

No. F. 11(4) Rev./6/14/pt./07

Jaipur, Dated : 21-02-18

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 100 of the Rajasthan land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of the 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Industrial Areas Allotment (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) The shall come into force at once.

2. Amendment of rule 3B.- In rule 3B of the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959, hereinafter referred to as the said rules, after the existing sub-rule (3), the following new sub-rule (4) shall be added, namely :-

(4) Notwithstanding anything contained in clause (a) and (b) of sub-rule (3) allotment of land for the following categories of Tourism unit projects, which are pending on the date of commencement of the Rajasthan Industrial Areas Allotment (Second Amendment) Rules, 2018 before the allotting authority shall be made on reserve price of land as specified in sub-rule (2), namely :-

(a) The tourism unit projects approved by the Department of Tourism for allotment of government land under the Rajasthan Tourism Unit Policy, 2007; or

(b) The tourism unit projects, involving allotment of government land for which MOUs have been signed under the aegis of the Resurgent Rajasthan-2015;

Provided that in case where more than one project has been approved or MOU signed for allotment of the same land or part thereof, preference shall be given to the project for which some

adjoining land, forming a part of the project is already available with the promotor, Where there is more than one project for such preferential treatment, there shall be competitive bidding within such projects deserving preferential treatment and where there is no case of such preferential treatment, there shall be competitive bidding within all the approved projects"

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, for the existing expression "industry", the expression "Industry other than tourism unit" shall be substituted.

By order of the Governor,

(S. R. Pilania)

Joint Secretary to the Government



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT**

No. F. 9(16) Rev./6/18/15

Jaipur, Dated : 22-03-18

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) read with sections 101 and 102 of the said Act and the proviso to section 34 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Permanent Allotment of Evacuee Agricultural Lands) Rules, 1963, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Permanent Allotment of Evacuee Agricultural Lands) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule.6.- In second proviso to sub-rule (4) of rule 6 of the Rajasthan Land Revenue (Permanent Allotment of Evacuee Agricultural Lands) Rules, 1963 :-

- (i) for the existing expression "25%", the expression "10%" shall be substituted ; and
- (ii) for the existing expression "12.5%", the expression "5%" shall be substituted.

By order of the Governor,

(Ramniwas Jat)

Joint Secretary to the Government

राजस्व मंडल समाचार

राजस्व मंडल ने रचा इतिहास

टीमवर्क ने दी मंडल को ऊंचाइयां-वी. श्रीनिवास

अजमेर 30 नवंबर। राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने राजस्व मंडल की सेवाओं को बेहतरीन एवं कारगर बनाने के हर संभव प्रयास किए। इसमें सभी के सहयोग से राजस्व मंडल की इतिहास में कीर्तिमान बनाया जा सका।

श्री श्रीनिवास को राजस्व मंडल की ओर से उनके दिल्ली केंद्र सरकार में स्थानांतरण के अवसर पर आयोजित अभिनंदन एवं विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाचार एवं डिजिटलाइजेशन की बदौलत जहां राजस्व मंडल ने कई ऊंचाइयां हासिल की वहीं याचिकाकर्ता, अभिभाषक, कृषक एवं आम जन समुदाय के लिए राजस्व न्यायालयों की प्रगति एवं कार्यों की क्रियान्वित की राह आसान बन सकी।

उन्होंने निष्ठा से कार्य करने वाले मंडल सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि उनकी ओर से भविष्य में भी राजस्व मंडल के लिए हर संभव सकारात्मक प्रयास जारी रहेंगे।

इस अवसर पर राजस्व मंडल सदस्य मोडू दान देथा ने अध्यक्ष श्रीनिवास के कार्यकाल को राजस्व मंडल के लिए स्वर्णिम बताया। स्वागत उद्बोधन उपनिबंधक श्री सुरेश सिंधी ने दिया। उनके अभिनंदन के मौके पर अजमेर संभागीय आयुक्त एल.एन. मीणा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के.के. शर्मा राजस्व मंडल सदस्य सूरजभान जैमन, इंद्र सिंह राव, राजेन्द्र कुमार, महावीर सिंह, मनोज कुमार नाग, धूकल राम कसवॉ, चिरंजी लाल दायमा, मोहनलाल नेहरा, राजस्व मंडल की अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्रीमती सीमा शर्मा, वित्तीय सलाहकार नरेन्द्र माथुर, उप रजिस्ट्रार नीतू यादव, भावना गर्ग व संयुक्त निदेशक भंवर लाल आदि ने भी श्रीनिवास का माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

राविरा का विमोचन

समारोह में मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित पत्रिका राविरा विशेषांक के 117वें अंक का विमोचन किया। इस अंक में राजस्व मंडल के प्रमुख निर्णय गतिविधियों एवं लोक अदालतों सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी को समाहित किया गया है।

राजस्व मंडल : डीपीसी से 46 तहसीलदार व 4 को कनिष्ठ सहायक पर पदोन्नति

अजमेर, 6 फरवरी। राजस्व मंडल में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 46 को तहसीलदार व 4 कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया।

राजस्व मंडल निबंधक ने बताया कि डीपीसी के तहत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नत कर 18 जनों को तहसीलदार बनाया गया वहीं 28 जनों को नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई है। वहीं 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

राजस्व मंडल में प्रकरणों का निस्तारण

रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद राजस्व मंडल में बीते वर्ष 2018 के दौरान रिकॉर्ड 9241 प्रकरणों का निस्तारण किया जा सका।

राजस्व मंडल में वर्षों से बकाया चले आ रहे प्रकरणों का एक वर्ष के दौरान बड़ी तादाद में निस्तारण मंडल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे लोक महत्व की दिशा में कारगर कदम कहा जा सकता है।

मंडल की ओर से बीते वर्ष निस्तारित विविध प्रकरणों में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के 4727, टीनैसी एक्ट, 1955 से संबंधित 4257, सीलिंग अधिनियम, 1973 के 49, कोलोनाइजेशन एक्ट 1945 के 183, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 के 7, जागीर, एबोलेशन एक्ट 1959 के 95, डायरेक्टर लेड रिकॉर्ड के मात्र फोरेस्ट एक्ट 1953, मातमी एक्ट 1945, जमींदारी बिस्वेदारी अधिनियम, 1959, भू-रूपान्तरण एक्ट से संबंधित एक-एक प्रकरण का निस्तारण किया जा सका।

आरसीएमएस सेवादों की ऑनलाईन मानिटरिंग

-ओ.पी. बंसल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.)

वर्ष 2018 में राजस्व मण्डल में राजस्व वादों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग के लिए आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से निम्न नवीन प्रयास किये गये-

1. वाद के निर्णित होने पर निर्णय ई-साईन किये जाने के उपरांत आरसीएमएस पोर्टल पर आम जनता के लिए ऑनलाईन किया जा रहा है।

2. राज्य की अधीनस्थ राजस्व न्यायलायों की मॉनिटरिंग का कार्य आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। यह मॉनिटरिंग कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मण्डल, राजस्व विभाग, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के स्तर से किया जा सकता है।

3. आम जनता के लिए वाद की स्थिति, कॉजलिस्ट की प्रति एवं प्रत्येक वाद के निर्णय की प्रति पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गयी है।

4. दिनांक 26.09.2017 से 18.02.2018 तक मण्डल द्वारा किये गये सभी निर्णयों की प्रति मण्डल की वेबसाईट एवं दिनांक 18.02.2018 से आदिनांक तक किये गये सभी निर्णयों की प्रति आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है।

5. आम जनता के लिए वाद के निर्णय को खोजने के लिए निम्न बिन्दुओं पर सर्च की प्रक्रिया उपलब्ध है।

1. वाद संख्या अनुसार
2. निर्णय की दिनांक के अनुसार
3. माननीय सदस्य के नाम के अनुसार
4. जिले के अनुसार
5. पीठ के अनुसार

पेड़ पिता हैं

जब भी देखता हूँ कोई पेड़
मुझे नजर आते हैं मेरे पिता,
ज़मीं से जल लेकर पेड़
सींचता है शाखाओं को,
अपने हौंसले को तना बनाकर
पेड़ खड़ा रहता है,
जड़ों के जरिये यथार्थ से
पेड़ जुड़ा रहता है,
मौसम की मार से झरती है पत्तियाँ
मगर पेड़ अपने जीवट से,
शाखाओं को फिर से कर देता है हरा भरा
जिन पर लगते हैं फूल,
फूलों को बना देता है फल
जिसमें भर देता है अपना सत्व,
और बीज में डाल देता है
एक पूरे पेड़ का जीवन-तत्व,
हाँ, मैं वही बीज हूँ
जिसे पिता ने पनपाया है
मेरा हर गुण पिता का सरमाया है,
प्रकृति, माँ के मानिंद होती है,
जिसकी कोख में पला हूँ मैं
जिसके सहारे मैं चला हूँ,
ये जीवन पेड़ और प्रकृति की सौगात है
मेरे वजूद की बस इतनी सी औकात है।

—टीकम बोहरा “अनजाना”

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर

Mob. : 09414077899

E-mail : tikam.bohra@gmail.com

राजस्व मंडल अजमेर के वरिष्ठ सदस्य सूरजभान जैमन गणतंत्र दिवस के मौके पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेन्द्र सिंह गौड़ को पारितोषिक प्रदान करते हुए।



राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण करते मण्डल के अधिकारी एवं कार्मिक





राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us :

Website : <http://landrevenue.rajasthan.gov.in/bor>

Email : bor-rj@nic.in